सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

आपका धर्य ही, आपके सौ दुखों का अंत है..!!

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–39 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, शुक्रवार 27 फरवरी 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए,

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट, कलेक्टर–एसएसपी ने किया निरीक्षण

25 लाख किसानों को बड़ी सौगात : 10 हजार करोड़ की प्रोत्साहन राशि सीधे खातों में भेजेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

नई दृष्टिबिंदु / बिलासपुर

28 फरवरी को ग्राम रहंगी में प्रस्तावित राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है, जहां कलेक्टर–एसएसपी ने स्थल निरीक्षण कर सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा कृषक उन्नति योजना के तहत राज्य के 25 लाख किसानों के बैंक खातों में 10 हजार करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि सीधे अंतरित की जाएगी, साथ ही करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण–भूमिपूजन होगा।

बिल्हा विकासखंड के ग्राम रहंगी में 28 फरवरी को प्रस्तावित मुख्यमंत्री के राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई हैं। कार्यक्रम को व्यवस्थित और सफल बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं एसएसपी रजनेश सिंह ने कार्यक्रम स्थल का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया और विभिन्न व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने मुख्य सभामंच, सांस्कृतिक मंच, विभागीय स्टॉल, बैठक व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, पार्किंग, हेलीपैड और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उपयुक्त स्थलों को चिन्हांकित किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी तैयारियां तय समयसीमा के भीतर पूरी की जाएं। मुख्यमंत्री के आगमन को ध्यान में रखते हुए खेल मैदान के समीप हेलीपैड निर्माण का निर्णय भी लिया गया है।

प्रशासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रहंगी के खेल मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को धान खरीदी के अंतर की प्रोत्साहन राशि वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। इसके साथ ही विभिन्न विभागों से जुड़े करोड़ों रुपये के विकास और निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी प्रस्तावित है।

अधिकारियों ने प्रस्तावित पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की कार्ययोजना तैयार की। वहीं एसएसपी रजनेश सिंह ने कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संभावित जनसमूह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक नियंत्रण तथा प्रवेश और निकास मार्गों को लेकर विस्तृत योजना बनाने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप अग्रवाल सहित लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सफल बनाने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं प्राथमिकता के साथ सुनिश्चित की जा रही हैं।

4 जिलों में संशोधित गाइडलाइन दरें आज से होंगी प्रभावशील

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से नवीन गाइडलाइन दरें लागू की गई हैं। राज्य शासन द्वारा जिला मूल्यांकन समितियों को निर्देश जारी किए गए थे कि स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुसार गाइडलाइन दरों में संशोधन संबंधी प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेजे जा सकते हैं। उक्त निर्देशों के अनुरूप दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा तथा बलरामपुर–रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुए। इन प्रस्तावों पर विचार हेतु महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलों से प्राप्त प्रस्तावित गाइडलाइन दरों का परीक्षण कर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया।

बैठक में समग्र परीक्षण के पश्चात केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा एवं बलरामपुर–रामानुजगंज जिलों की जिला मूल्यांकन समितियों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के प्रस्तावों का अनुमोदन प्रदान किया गया। केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित नवीन गाइडलाइन दरें उपरोक्त चारों जिलों में 27 फरवरी 2026 से प्रभावशील होंगी। आम नागरिक एवं संबंधित हितधारक नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों तथा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।अन्य जिलों की संशोधित गाइडलाइन दरें भी शीघ्र जारी की जाएंगी।

शराब दुकान के विरोध में उग्र हुआ जनआंदोलन, पूर्व विधायक छन्नी साहू ग्रामीणों के साथ सड़क पर

नई दृष्टिबिंदु / छुरिया

गेंदाटोला में संचालित शराब दुकान के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश अब खुलकर सामने आ गया है। मुख्य मार्ग पर स्थित इस दुकान को हटाने की मांग को लेकर पूर्व विधायक छन्नी साहू ग्रामीणों के साथ सड़क पर उतरीं और विरोध प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में मौजूद ग्रामीणों ने दुकान को तत्काल बंद करने या अन्यत्र स्थानांतरित करने की मांग की।

पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि शराब दुकान के मुख्य मार्ग पर होने से महिलाओं और स्कूली छात्राओं को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि नशे की हालत में कुछ लोग सड़क पर वाहन खड़े कर देते हैं और आने–जाने वाली छात्राओं एवं महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। उन्होंने दावा किया कि कई बार आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर महिलाओं को परेशान किया जाता है, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है।

गौरतलब है कि गेंदाटोला क्षेत्र आसपास के 20–25 गांवों के लिए प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता है। बाजार और दैनिक जरूरतों के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण यहां आते–जाते हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सड़क किनारे शराब दुकान होने के कारण आसपास गंदगी भी बढ़ रही है। खाली बोतलें, डिस्पोजल सामग्री और पानी के पाउच सड़क पर फेंके जाने से राहगीरों, मजदूरों और विशेषकर महिला श्रमिकों को असुविधा झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि राजस्व वृद्धि के उद्देश्य से बंद पड़ी शराब दुकानों को दोबारा खोला जा रहा है, जबकि इससे जुड़े सामाजिक प्रभावों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन सामने नहीं आया है।

नगरी निकायों को मिली 51 करोड़ की राशि, होली का रंग नहीं पड़ेगा फीका

कर्मचारियों के चेहरे पर लौटेगी मुस्कान, ठेकेदारों को भी होगा आवश्यक भुगतान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

इस बार नगर पालिका निगम और नगरीय निकायों में होली का रंग फीका नहीं पड़ेगा। वर्षों बाद ऐसा दृश्य बनने जा रहा है, जब प्लेसमेंट कर्मचारियों, निर्मित कर्मचारियों से लेकर विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदारों तक को त्योहार से पहले भुगतान मिलने की ठोस तैयारी की गई है। नगरी प्रशासन ने समय पर वेतन और देयकों के भुगतान के लिए कमर कस ली है, ताकि कमर्चारी और सहयोगी बिना किसी चिंता के रंगों का त्योहार मना सकें।

नगर पालिका निगमों और नगर पंचायतों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए इस बार होली खुशियों का पैगाम लेकर आ रही है। नगरी प्रशासन द्वारा बीते दिनों लगभग 51 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे प्लेसमेंट कर्मचारियों, निर्मित कमर्चारियों और अन्य श्रेणी के कर्मियों का भुगतान समय पर किया जा सके। यह राशि नगरी प्रशासन एवं विकास विभाग के माध्यम से नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई जा रही है।

सूत्रों के अनुसार, यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि त्योहारों के समय कर्मचारियों और ठेकेदारों पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। होली जैसे बड़े पर्व पर सभी की यही उम्मीद रहती है कि मेहनत की कमाई समय पर हाथ में आए, ताकि परिवार के साथ खुशियां साझा की जा सकें। इस बार नगरी प्रशासन ने इसी भावना को ध्यान में रखते हुए भुगतान की प्रक्रिया को प्राथमिकता में रखा है।

ठेकेदारों को भी मिलेगी राहत

केवल कर्मचारी ही नहीं, बल्कि विकास कार्यों से जुड़े ठेकेदारों को भी इस पहल का सीधा लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक 15वां वित्त आयोग की राशि, मूलभूत सुविधा एवं अधोसंरचना मद सहित विभिन्न मदों से लंबित भुगतान निपटाने की योजना बनाई गई है। इसके लिए सभी आयुक्तों, मुख्य नगर पालिका अधिकारियों और लेखा शाखाओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि त्योहार से पहले अधिकतम देयकों का भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

त्योहार से पहले भरोसे की बहाली

नगरीय निकायों में काम करने वाले कमर्चारी और ठेकेदार लंबे समय से भुगतान को लेकर असमंजस में रहते आए हैं। ऐसे में होली से पहले यह आर्थिक सहयोग न केवल राहत देने वाला है, बल्कि शासन और प्रशासन के प्रति भरोसे को भी मजबूत करता है। कर्मचारियों का कहना है कि समय पर भुगतान मिलने से वे पूरे मन से होली मना पाएंगे और इसका सकारात्मक असर कामकाज पर भी पड़ेगा।

कुल मिलाकर इस बार होली सिर्फ रंगों की नहीं, बल्कि समय पर भुगतान से मिलने वाली राहत और संतोष की भी होगी। नगरी प्रशासन की इस पहल से यह साफ संकेत मिल रहा है कि त्योहारों पर कर्मचारियों और सहयोगियों की जरूरतों को समझते हुए प्रशासन अब ज्यादा संवेदनशील और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यही वजह है कि इस बार नगरीय निकायों में होली का रंग पूरी तरह चटख और खुशियों से भरा रहने वाला है।

11 नगर निगमों को वेतन के लिए 25.05 करोड़

प्रदेश के 11 नगर निगमों को कुल 25 करोड़ 5 लाख 34 हजार रुपये की राशि वेतन एवं चुंगी क्षतिपूर्ति मद में प्रदान की गई है। नगर पालिक निगम भिलाई को 4 करोड़, बिलासपुर को 5 करोड़, दुर्ग को 1 करोड़ 65 लाख 92 हजार, राजनांदगाँव को 3 करोड़, जगदलपुर को 1 करोड़ 50 लाख, अंबिकापुर को 3 करोड़, चिरमिरी को 2 करोड़, रिसाली को 2 करोड़, बीरगांव को 54 लाख 55 हजार, धमतरी को 1 करोड़ 7 लाख एवं भिलाई–चरोदा को 1 करोड़ 27 लाख 87 हजार रुपये जारी किए गए हैं। नगर निगमों में यह राशि मुख्य रूप से नियमित कर्मचारियों, स्वच्छता कर्मियों एवं संविदा कर्मचारियों के वेतन भुगतान तथा चुंगी समाप्त होने से उत्पन्न राजस्व अंतर की भरपाई हेतु उपयोग की जाएगी। इसके अलावा प्रदेश के सभी 14 नगर निगमों को चुंगी क्षतिपूर्ति के अंतर्गत 7 करोड़ 51 लाख 55 हजार 420 रुपये भी आबंटित किए गए हैं।

नगर पालिकाओं को 16.48 करोड़ व नगर पंचायतों को 10.17 करोड़

नगरीय प्रशासन विभाग ने प्रदेश के 38 नगर पालिका परिषदों में 16 करोड़ 48 लाख की राशि तथा 85 नगर पंचायतों को कुल 10 करोड़ 17 लाख रुपये से अधिक की राशि होली के पूर्व निकाय कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए आबंटित की है। छोटे एवं मध्यम नगरीय निकायों के लिए यह वित्तीय सहायता अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्रदेश के सभी 54 नगर पालिकाओं को भी चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि दी गई है। इसके लिए 2 करोड़ 8 लाख 52 हजार 17 रुपए का आबंटन जारी किया गया है। इसके अलावा सभी 124 नगर पंचायतों को एक करोड़ 54 लाख 31 हजार 55 रुपए की मासिक चुंगी क्षतिपूर्ति राशि दी गई है।

विभाग द्वारा आज आबंटित राशि से नगरीय निकायों में कार्यरत हजारों कर्मचारियों को होली के पूर्व वेतन प्राप्त होगा। इससे निकायों में स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, प्रकाश व्यवस्था एवं अन्य शहरी सेवाओं में निरंतरता बनी रहेगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने स्पष्ट किया है कि आबंटित राशि का उपयोग निर्धारित मदों में ही किया जाएगा। सभी निकायों को वित्तीय नियमों का पालन करते हुए व्यय विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। चुंगी क्षतिपूर्ति मद से वेतन के लिए 51.71 करोड़ एवं नियमित चुंगी क्षतिपूर्ति के रूप में 11.14 करोड़, इस प्रकार कुल 62.85 करोड़ रुपये से अधिक की राशि का होली के पहले आबंटन नगरीय निकायों के लिए बड़ी राहत है।

चुंगी क्षतिपूर्ति मद के माध्यम से निकायों को समस्त कर्मचारियों के वेतन भुगतान करने में स्थिरता आएगी और शहरी प्रशासन को मजबूती मिलेगी। राज्य सरकार की यह पहल शहरी सेवाओं को निरंतर और प्रभावी बनाए रखने की दिशा में एक सशक्त कदम है।

अरुण साव, उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री

दो दिवसीय 'छत्तीसगढ़ ज्ञान सभा', विकसित भारत 2047 की दिशा में शिक्षा पर होगा मंथन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण के समन्वय को केंद्र में रखते हुए श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में दो दिवसीय छत्तीसगढ़ ज्ञान सभा – विकसित भारत स्वर्णिम युग की ओर 2047 का आयोजन 28 फरवरी एवं 01 मार्च 2026 को किया जाएगा। यह आयोजन छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग एवं शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के संयुक्त सहयोग से होगा।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूर्व सरकार्यवाह सुरेश भैय्याजी जोशी होंगे। ज्ञान सभा का आयोजन श्री शंकराचार्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, जुनवानी, भिलाई में किया जाएगा। प्रथम दिवस कार्यक्रम प्रातः 10.30 से सायं 4.30 बजे तक तथा द्वितीय दिवस प्रातः 10.30 से दोपहर 1.00 बजे तक संपन्न होगा।

शिक्षा से विकसित भारत की राह: इस ज्ञान सभा का मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के परिप्रेक्ष्य में विद्यालयीन, उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा की भूमिका पर गंभीर विमर्श करना है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, कौशल आधारित शिक्षा, खेल–खेल में शिक्षण, मातृभाषा में शिक्षा, मानवीय मूल्यों एवं भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षण मॉडल जैसे विषयों पर विशेषज्ञ अपने विचार साझा करेंगे।

प्रमुख संरक्षक व शिक्षाविद होंगे शामिल: कार्यक्रम के मुख्य संरक्षक के रूप में शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉ. अतुल कोठारी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आईपी मिश्रा एवं आयोग के अध्यक्ष डॉ. वीके गोयल मार्गदर्शन देंगे। वहीं संरक्षकों में प्रो. राजीव प्रकाश, डॉ. आलोक कुमार चकवाल तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक ओमप्रकाश शर्मा शामिल रहेंगे।

शोध, नवाचार और उद्यमिता पर जोर : ज्ञान सभा में उच्च शिक्षा में अनुसंधान, नवाचार एवं उद्यमिता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु छात्र तैयारी, भारतीय ज्ञान परंपरा आधारित शिक्षा प्रणाली के संवर्धन तथा भारतीय इतिहास के समग्र दृष्टिकोण जैसे विषयों पर विशेष सत्र होंगे। साथ ही विद्यालयीन शिक्षा में तकनीक, डिजिटल कक्षा, सतत मूल्यांकन और शिक्षक की बदलती भूमिका पर भी विचार मंथन किया जाएगा।

शोध पत्र व प्रदर्शनी का अवसर: कार्यक्रम के अंतर्गत शोधार्थियों व शिक्षाविदों से विद्यालयीन एवं उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों पर शोध पत्र आमंत्रित किए गए हैं। केवल 200 से 300 शब्दों के Abstract प्रकाशित किए जाएंगे। शोध पत्र भेजने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित है। इसके अलावा 28 फरवरी व 01 मार्च को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं उत्कृष्ट शैक्षणिक कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी।

आयोजकों ने शिक्षकों, विद्यार्थियों, शिक्षाविदों एवं समाज के प्रबुद्ध नागरिकों से इस ज्ञान सभा में सहभागिता कर शिक्षा के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने की अपील की है। कार्यक्रम को पर्यावरण अनुकूल रखते हुए प्लास्टिक उपयोग न करने का भी आग्रह किया गया है।

उपलब्धि टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने जरूरत की पूरी मात्रा की स्पेशल ग्रेड स्टील की आपूर्ति की

स्वदेशी सेल स्टील से बना है भारतीय नौसेना बेड़े में शामिल होने जा रहा आईएनएस अंजदीप

नई दृष्टिबिंदु / नई दिल्ली

देश की सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी इस्पात उत्पादक और महारत्न कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा निर्मित आईएनएस अंजदीप (INSAnjadip) के लिए जरूरत की पूरी मात्रा की स्पेशल ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। आईएनएस अंजदीप भारतीय नौसेना में शामिल होने जा रहा तीसरा एंटी–सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) कार्वेट है। इससे पहले पिछले साल आईएनएस अरनाला और आईएनएस एंड्रोथ भी शामिल किए जा चुके हैं।

नौसेना के पुराने होते 'अभय–श्रेणी' के जहाजों को बदलने के लिए इन ASW-SWC कार्वेट का निर्माण स्वदेशी रूप से किया जा रहा है। इस रणनीतिक प्रयास में योगदान देते हुए, सेल (SAIL) ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा बनाए जा रहे आठ ASW-SWC कार्वेट के लिए लगभग 3,500 टन विशेष–ग्रेड स्टील की पूरी मात्रा की आपूर्ति की है। इस स्टील की आपूर्ति सेल के बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्रों से की गई है, जो देश की डोमेस्टिक सप्लाई चेन की मजबूती को रेखांकित करता है।

यह उपलब्धि रक्षा विनिर्माण में भारत की आत्मनिर्भरता को आगे बढ़ाने, आयात पर निर्भरता कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करने के प्रति सेल की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। पिछले कुछ वर्षों में, सेल ने रक्षा स्वदेशीकरण में देश की विशेष–ग्रेड स्टील की जरूरतों को लगातार पूरा किया है और आईएनएस विक्रांत, आईएनएस उदयगिरि, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत जैसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए स्टील की आपूर्ति की है।

डुडेरा और पुरैना में दो दिन नहीं खुलेगा नल

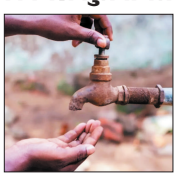

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

नगर पालिक निगम रिसाली के डुडेरा व पुरैना क्षेत्र के 5 वार्डों में जल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। मोरिद स्थित 6 एम एल डी जल शोधक संयंत्र में तकनीकी खराबी आने के कारण मरम्मत कार्य करने शट डाउन लिया जा रहा है। इस वजह से शुक्रवार और शनिवार को पूर्ण रूप से जल प्रदाय प्रभावित रहेगा। जल कार्य विभाग के सहायक अभियंता अखिलेश गुप्ता ने बताया कि प्रभावित क्षेत्र में पानी टैंकर से आपूर्ति की जाएगी।

महत्वपूर्ण सूचना! हमारे पाठकों के लिए
सांध्य दैनिक नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
सांध्य दैनिक नई दृष्टिबिंदु का E-Paper भी तैयार है। प्रतिदिन शाम 4:00 बजे पेपर नई दृष्टिबिंदु के गुगल के साइट Nayi Drishtibindu पर अपलोड हो जाता है। सभी पाठकों से आग्रह है कि प्रतिदिन शाम 4:00 बजे साइट पर Nayi Drishti bindu E-Paper सर्च कर ई पेपर देख सकते हैं।
Google
NAYI DRISHTIBINDU E-PAPER
शाम 4 बजे से पढ़े

आत्मिक स्मृति व जगत नियंता परमात्मा की याद में कर्म कर जीवन सरल बनाएं-ब्रह्माकुमार प्रकाश

हाथों से काम करें मन,बुद्धि से परमात्मा को याद करे, सब प्रभु अमानत समझ कर कर्म करने वाला ही कर्मयोगी और सहज राजयोगी है

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

पत्ते पत्ते का पता है परमात्मा को इस मनुष्य रूपी कल्पवृक्ष का, भगवान को सर्वज्ञ जानीजाननहार कहते हैं, वह इस मनुष्य रूपी कल्पवृक्ष के बीज रूप है। इस सृष्टि पर हम सभी आत्माएं अशरीरी (विदेही) आए थे, अशरीरी (विदेही) बनकर ही जाना है।

उक्त बातें प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय द्वारा सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू से मीडिया विंग के उपाध्यक्ष तथा ज्ञान अमृत मासिक पत्रिका के संपादक राजयोगी ब्रह्माकुमार आत्म प्रकाश भाई जी ने भिलाई प्रवास पर कही। आपने कर्मयोग के बारे में बताया कि हाथों से काम करें मन,बुद्धि से परमात्मा को याद करे, सब प्रभु अमानत समझ कर कर्म करने वाला ही कर्मयोगी और सहज राजयोगी है। दो बातों का अटेंशन सदा रखो,कर्म करते स्वयं को ट्रस्टी समझ, आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर कर्म करना है जगत नियंता परमात्मा करनकारवनहार की स्मृति से कर्म करो।

आत्म अभिमानी अर्थात जिन्हें अपने पद, धन,शिक्षा,रूप,गुणों,विशेषताओं का अभिमान ना हो। इस संसार में रहते हैं कमल फूल समान न्यारे रहो, संसार में व्याप्त बुराइयां का प्रभाव न पड़े। मनसा वाचा कर्मणा को श्रेष्ठ बनाएं। हमारा मन शांत निर्मल हो, वाणी मधुर मीठी हो, कर्मणा हमारे कर्म सभी को सुख देने वाले हो। सतयुग में एक राज्य एक धर्म एक भाषा थी जिसको रामराज्य और प्राचीन भारत,स्वर्णिम भारत स्वर्ग कहा जाता था। भारत को बहुत ही मान देते हैं, अभी परमात्मा द्वारा सृष्टि पर पुनः

राम राज्य की स्थापना का कार्य चल रहा है।

जिनकी दिल बड़ी सच्ची साफ दिल है उनके लिए असंभव कार्य भी संभव हो जाता है, जो कार्य ब्रह्माकुमारी बहनें पूरे विश्व में कर रही हैं ,यह प्रत्यक्ष उदाहरण ब्रह्माकुमारी संस्था का। इनकी एकता और परमात्मा में दृढ़ निश्चय और विश्वास से इनका हर कार्य सफल होता है। आपने कहा कि अपनी और दूसरों की विशेषताओं, गुणों को सामने रखो कमजोरी को नहीं, कमजोरी को ज्यादा नहीं सोचो खुशी में आगे बढ़ते जाओ।

इस अवसर पर राजयोग भवन में पुनःनिर्मित भोलेनाथ शिव बाबा की भंडारी का रिबन काट कर, दीप प्रज्वलंन कर ब्रह्माकुमार आत्म प्रकाश भाई, इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका ब्रह्माकुमारी हेमलता दीदी जी, ब्रह्माकुमारी आशा दीदी जी एवं भिलाई के सभी सेवा केंद्रों की प्रमुख ब्रह्माकुमारी बहनों ने परमात्म याद में रह कर उद्घाटन किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ब्रह्मा वत्स उपस्थित रहे।

खास खबर

एसईएसबीएफ में जमा राशी का निवेश कर्मचारियों के सहमति से ही एनपीएस में डाले सेल प्रबंधन-रणधीर

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बीएसपी अनाधिशासी कर्मचारी संघ के कार्यकारी अध्यक्ष रणधीर कुमार ने एसईएसबीएफ ट्रस्ट के चेयरमैन सह अधिशासी निदेशक एच आर राजीव पाण्डेय को पत्र लिखकर एसईएसबीएफ ट्रस्ट में कर्मचारियों के जमा धन का एनपीएस में निवेश करने से पहले कर्मचारियों की लिखित सहमति लेने का मांग किया है। 2 फरवरी 2026 को कोलकाता में एसईएसबीएफ ट्रस्ट की ट्रस्टियों की 50वीं बैठक तथा मैनेजिंग ट्रस्टियों की 86 बैठक आयोजित हुई है ।जिसमें अव्यवहारिक तथा गलत प्रक्रिया के तहत निर्णय लिया गया है ।जिसका विवरण निम्नलिखित है -कर्मचारियों से बगैर सहमति लिए ही एसईएसबीएफ मद में जमा राशी को नेशनल पेंशन ट्रस्ट में हस्तांतरित करने का निर्णय-चुँकी एसईएसबीए ट्रस्ट में जमा धन कर्मचारियों के वेतन से कटौती का हिस्सा है अतः बगैर उनकी सहमति या असहमति जाने तथा फर्जी और गैर निर्वाचित यूनियन प्रतिनिधियों की सहमती से एसईएसबीएफ में जमा राशी को एनपीएस में हस्तांतरित करने का निर्णय पुर्णतः तानाशाही भरा तथा एकतरफा है ।

सरकार की असहमती-खुद एसईएसबीएफ ट्रस्ट की 02 फरवरी 2026 की मीटिंग के आपके हस्ताक्षर से जारी मिनट्स में जिक्र किया गया है कि एसईएसबीएफ का गठन सेल कार्मिकों को अतिरिक्त पेंशन देने के लिए 1989 में किया गया था परंतु बाद में सरकार के गाईडलाईन तथा सेल पेंशन ट्रस्ट के गठन के बाद एसईएसबीएफ फंड को निवेश फंड के रुप में परिवर्तित कर दिया गया । फिर एकतरफा निर्णय लेकर जमा राशी को एनपीएस में जमा करने का निर्णय लिया गया है जो कि पुर्णतः गलत निर्णय है । जमा धन का मालिकाना हक-एसईएसबीएफ ट्रस्ट में जमा धन शत प्रतिशत कार्मिकों का है जो उनके वेतन से कटौती किया गया है । उसमें सेल या उसकी यूनिट प्रबंधन का 1% भी योगदान नही है । उस धन के निवेश का निर्णय हमेशा कार्मिकों के सहमति के बाद ही लिया जाना है ।

गलत निर्णय का आधार : कार्मिकों से एक मामले में सहमति लेना तथा दूसरे मामले में खुद निर्णय लेना — यह आश्चर्यजनक है कि अप्रैल 2026 से बेसिक/ डीए के 2% अंशदान एनपीएस में करने पर कार्मिकों से सहमति ली जानी है परंतु पिछले जमा अंशदान को कार्मिकों के बगैर सहमति के ही एनपीएस में भेजने का निर्णय लिया गया है। एसईएसबीएफ ट्रस्ट में अवैध / गैर निर्वाचित/गैर रिकॉगनाईज्ड कर्मचारी प्रतिनिधियों की बहुतायत संख्या — 02 फरवरी 2026 को हुई एसईएसबीएफ ट्रस्ट की बैठक में शामिल 15 यूनियन प्रतिनिधियों में से केवल 3 ही निर्वाचित तथा रिकॉगनाईज्ड यूनियनों के प्रतिनिधि है जो राउरकेला इस्पात संयंत्र , वीआईएसएल भद्रावति तथा सलेम इस्पात संयंत्र से सदस्य है । शेष 12 प्रतिनिधि न तो निर्वाचित है तथा न ही उनका यूनियन रिकॉगनाईज्ड है तथा न ही आज तक सेल प्रबंधन और श्रम मंत्रालय द्वारा सेल स्तर पर सभी यूनियनो का सदस्यता सत्यापन हुआ है जिससे पता चल सके कि किस यूनियन के पास कितने सेल कर्मचारी सदस्य है। यही हालत तीनो मैनेजिंग ट्रस्टियों का भी है ।

दूसरी तरफ एनजेसीएस में मनोनित तथा गैर निर्वाचित : यूनियन प्रतिनिधियों का मामला माननीय दिल्ली ऊच्च न्यायालय में सुनवाई की अवस्था में है वही सेल की बोकारो, भिलाई तथा इस्को बनर्पुर में रिकॉगनाईज्ड यूनियन का मामला क्रमशः झारखण्ड ऊच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय तथा कोलकाता उच्च न्यायालय में सुनवाई की अवस्था में है। इन तथ्यो से स्पष्ट है कि वतर्मान एसईएसबीएफ ट्रस्ट पुर्णतः अवैध यूनियन प्रतिनिधियों से भरा हुआ है अतः इन सदस्यों द्वारा लिया गया निर्णय भी पूर्णतः अवैध है । पत्र की प्रतिलिपि, सेल चेयरमैन, डायरेक्टर फाईनेंस तथा सचिव इस्पात मंत्रालय को भी भेजा गया है । उसी के आलोक में, रणधीर कुमार ने मांग किया है कि एसईएसबीएफ ट्रस्ट में जमा धन पुर्णतः कमचारियों का है , उस धन में सेल प्रबंधन का 1% भी योगदान नही है । अतः एसईएसबीएफ ट्रस्ट में जमा धन का निर्णय लेने का अधिकार केवल उसके हिस्सेदार कार्मिकों का है । इसलिए सेल प्रबंधन एनपीएस में भेजने से पहले कार्मिकों से सहमती पत्र ले नही तो विवश होकर यूनियन सभी ट्रस्टियों के विरुद्ध न्यालय की शरण में जायेगी ।

एसईएसबीएफ में जमा धन कर्मचारियों का है , मैनेजमेंट सिर्फ संरक्षक है , मालिक नही कि वह जमा धन के निवेश पर मनमाना निर्णय ले । वही एसईएसबीएफ में शामिल 15 में से 12 यूनियन प्रतिनिधि कर्मचारियों द्वारा चयनित प्रतिनिधि नहीं है ।

रणधीर कुमार , कार्यकारी अध्यक्ष , बीएकेएस भिलाई

भारतीय मजदूर संघ ने श्रमिकों के मांगों को लेकर निकाली रैली

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम सौंपा ज्ञापन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारतीय मजदूर संघ का 21वां अखिल भारतीय त्रैवार्षिक तीन दिवसीय अधिवेशन 6, 7 एवं 8 फरवरी 2026 को पुरी (भगवान जगन्नाथ धाम) में संपन्न हुआ। अधिवेशन में देशभर से आए प्रतिनिधियों ने श्रमिकों से जुड़े ज्वलंत मुद्दों पर गहन चर्चा की तथा सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया।

अधिवेशन से पूर्व भारतीय मजदूर संघ के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मंत्री से मुलाकात कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा था। मंत्री द्वारा शीघ्र समाधान का भरोसा दिए जाने के बावजूद मांगें पर ठोस कार्रवाई नहीं होने से 25 फरवरी 2026 को देशभर में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया।

धरना, रैली और ज्ञापन

अखिल भारतीय अधिवेशन में तय दिशानिर्देशों के अनुरूप भारतीय मजदूर संघ जिला दुर्ग एवं संबद्ध यूनियनों द्वारा पुराना बस स्टैंड में धरना दिया गया, जिसके पश्चात कलेक्टरेट तक रैली निकालकर ज्ञापन सौंपा गया।

कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री दिनेश पांडे, जिला मंत्री हरिशंकर चतुर्वेदी, जिला अध्यक्ष मिथिलेश विश्वकर्मा, रवि चौधरी, स्वायत्तशासी कमचारी संघ के प्रदेश महामंत्री अनिल सिंह, संजय मिश्रा, शशि यादव, ईश्वर वर्मा, दुर्गेश गुप्ता, शशि भूषण मोहंती, राजू बक्शी, साक्षी वर्मा, चित्रलेखा चंद्रकार, चंचल राजपूत, सूरज सारथी, दामिनी भुवाल, अनिता, वसुंधरा चौरे, देवेंद्र चंद्राकर, बी.एस. राजपूत, शिवेंद्र दुबे, रवि शंकर सिंह, अशोक देवांगन, रामवृक्ष यादव, गोपाल सिन्हा, विवेका रंगनाथ, नलनीश मिश्रा, वाल्मीकि सिंह सहित सैकड़ों कमचारी उपस्थित रहे। भारतीय मजदूर संघ ने स्पष्ट किया कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

प्रधानमंत्री के नाम प्रमुख मांगें

सभी सेक्टरों के श्रमिकों पर श्रम कानून बिना किसी छूट के समान रूप से लागू किए जाएं। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एवं ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 में श्रमिक चिंताओं का समाधान किया जाए। त्रिपक्षीय तंत्र का पुनरुद्धार कर इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस शीघ्र आयोजित की जाए। EPS-95 में न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़ाकर 7500 प्रतिमाह महंगाई राहत सहित की जाए। EPF वेतन सीमा 15000 से बढ़ाकर 30000 तथा ESIC सीमा 21000 से बढ़ाकर 42000 की जाए। बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के तहत पात्रता व गणना सीमा में वृद्धि की जाए। संविधान की भावना के अनुरूप स्कीम वर्कर एवं ठेका श्रमिकों को स्थायी किया जाए। आम भर्ती पर लगी रोक हटाकर गारंटीड रोजगार सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के नाम प्रमुख मांगें

सभी उद्योगों में यूनियन के साथ वेतन समझौता लागू हो। रात्रि पाली, आवास एवं वाहन भत्ता दिया जाए। ठेका श्रमिकों को वैतनिक साप्ताहिक अवकाश मिले। औद्योगिक क्षेत्रों को सवर्सुविधायुक्त एवं प्रदूषण मुक्त बनाया जाए, साथ ही हॉस्टल निर्माण हो। ई-रिक्शा चालकों के लिए स्टैंड व चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाए। निजी अस्पतालों के नर्सिंग व अन्य स्टाफ के लिए वेतनमान, लंच व टी टाइम तय किया जाए। निजी विद्यालयों के शिक्षकों व कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान मिले। औद्योगिक व ट्रांसपोर्ट क्षेत्रों में ड्राइवरों के लिए रैन बसेरा, कैंटीन व रेस्ट रूम का निर्माण हो। भवन निर्माण मजदूर संघ को नियोजन प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार पुनः बहाल किया जाए। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए। सड़क सुरक्षा समितियों में प्राइवेट ट्रांसपोर्ट मजदूर महासंघ के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। नगरीय निकायों में 2004 के बाद नियुक्त कमर्चारियों के लिए पुरानी पेंशन व पदोन्नति की मांग।

PHE विभाग में भ्रष्टाचार के आरोप SDO को बर्खास्त करने की मांग

प्रशासन से मांग

तीन दिन में कार्रवाई नहीं होने पर पुतला दहन व अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

जिले के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। इस संबंध में प्रदेश युवा कांग्रेस एवं जिला युवा कांग्रेस दुर्ग के मार्गदर्शन में कार्यकर्ताओं ने दीपांकर साहू के नेतृत्व में जिलाधीश कार्यालय दुर्ग को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि दुर्ग PHE विभाग में ठेकेदारों से अंतिम देयक (बिल) बनाने से पहले कमीशन की मांग की जा रही है। आरोपों के अनुसार SDO धमधा प्रकाश सिंह ठाकुर द्वारा, कार्यपालन अभियंता (EE) के निर्देशों के बावजूद ठेकेदारों के बिल लंबित रखे जा रहे हैं तथा मुख्य अभियंता के नाम का हवाला देकर दबाव बनाया जाता है। इसके साथ ही शिकायत करने पर ठेकेदारों को झूठे प्रकरणों में फंसाने की धमकी दिए जाने का भी आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं होने से भ्रष्टाचार को संरक्षण मिल रहा है।

युवा कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि तीन दिवस के भीतर SDO के विरुद्ध कठोर कार्रवाई नहीं की गई और ठेकेदारों को परेशान करना बंद नहीं हुआ, तो

27 फरवरी 2026 को दोपहर 01:00 बजे PHE कार्यालय के सामने PHE मंत्री अरुण साव का पुतला दहन किया जाएगा। इसके बाद 9 मार्च 2026 से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन PHE कार्यालय के समक्ष शुरू किया जाएगा, जो SDO की बर्खास्तगी तक जारी रहेगा। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि आंदोलन की स्थिति बनी, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी।

युवा कांग्रेस ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर दोषी अधिकारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए, ताकि विभाग में पारदर्शिता बहाल हो और ठेकेदारों को न्याय मिल सके।

ई-सिटी बस जल्द, सीधे रायपुर एम्स, डीकेएस तक जा सकेंगे

भिलाई। दुर्ग-भिलाई सहित आसपास क्षेत्र के लोगों को सस्ती परिवहन सुविधा जल्द उपलब्ध होगी। आने वाले कुछ महीने में शहर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक सिटी बसें दौड़ेंगी। इन बसों का रूट तैयार किया जा रहा है। पुरानी योजना के तहत जिला प्रशासन ने 13 रूट बनाए थे, जिसमें अब कुछ और नए रूट तय करने पर विचार किया जा रहा है। ई-सिटी बस सेवा से लोग सीधे रायपुर एम्स, डीकेएस अस्पताल, घड़ी चौक तक का सफर कर सकेंगे। दूसरी दिशा में राजनांदगांव तक के लिए भी सिटी बस चलाने की योजना है। आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में ई-बस के रूट को लेकर चर्चा की गई। आयुक्त राजीव पांडेय ने कहा कि दुर्ग से सीधे एम्स और डीकेएस अस्पताल रायपुर जाने का भी रूट होना चाहिए। इसके लिए रूट तैयार किये जायें।

मंत्री गजेन्द्र यादव की उपस्थिति में दुर्ग निगम के पार्षदों ने देखी विधानसभा की कार्यवाही

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग शहर विधानसभा से दुर्ग नगर निगम के पाषदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा का भ्रमण किया। इस दौरान पाषदी ने विधानसभा में बजट सत्र की कार्यवाही को नजदीक से देखा और संसदीय प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त किये।

भ्रमण के दौरान पाषदी ने विधानसभा परिसर दर्शक दीर्घा, पुस्तकालय तथा केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव के कक्ष पहुँचे और उनसे सौजन्य मुलाकात कर विभागीय कार्यों की जानकारी लिए। राज्य की राजनीति, विधायी प्रक्रिया और उनके महत्व के बारे में जानकारी लिए। उन्होंने सभी पाषदी को अपने क्षेत्र में कार्य के साथ-साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दी। इस दौरान शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव ने दुर्ग निगम के पाषदी को विधानसभा में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र में होने वाले कार्यवाही की जानकारी दिए। इसके पश्चात विधानसभा सत्र की कार्यवाही से अवगत कराये।

इस अवसर पर दुर्ग निगम के पाषदी ने कहा कि यह भ्रमण उनके लिए सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर था। इससे उन्हें राज्य की राजनीतिक संरचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। मंत्री गजेन्द्र यादव ने विधानसभा भ्रमण के दौरान प्रश्नकाल में सवाल पूछने और आने की प्रक्रिया, ध्यानाकर्षण में जनता के मुद्दों को सदन में रखने की जानकारी साझा किये।

विधानसभा भ्रमण के दौरान महापौर श्रीमति अलका बाघमार, पार्षद देवनारायण चंद्राकर, चंद्रशेखर चंद्राकर, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, नीलेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, श्रीमति रंजीता पाटिल, श्रीमति सुरुचि उमरे, युवराज कुंजाम, श्रीमति हर्षिता जैन, श्रीमति सावित्री दामाहे, जैन सहित अन्य पार्षदगण उपस्थित रहे।

खेल गतिविधियां व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन व सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करती

अंतरविभागीय खेल प्रतियोगिता जोश-2026 का सफल आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग द्वारा 02 से 16 फरवरी 2026 तक अंतरविभागीय खेल प्रतियोगिता 'जोश-2026' का उत्साहपूर्वक आयोजन किया गया। लगभग एक दशक के अंतराल के पश्चात आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों, कार्मिकों एवं अधिकारियों के मध्य टीम भावना, सकारात्मक सोच, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं संगठन के प्रति जुड़ाव की भावना को सुदृढ़ करना था।

प्रतियोगिता के अंतर्गत 2 फरवरी से 14 फरवरी तक समस्त इनडोर खेलों का आयोजन हॉस्टल क्रमांक-2 एवं 3 में किया गया, जबकि 16 फरवरी को जयंती स्टेडियम में आउटडोर खेल प्रतियोगिताएं संपन्न हुईं। इस आयोजन में सभी ट्रेड अपरेंटिस, एसीटी, ओसीटी प्रशिक्षणार्थियों के साथ-साथ विभागीय कार्मिकों एवं अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई।

समापन समारोह में कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार, महाप्रबंधक प्रभारी (एच.आर.झएल. एंड डी.) संजीव श्रीवास्तव, महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन) जे.एन. ठाकुर, उप महाप्रबंधक (एच.आर.झएससीसी) राजेन्द्र प्रसाद, महाप्रबंधक (एच.आर.झएल. एंड डी.) मुकुल सहारिया तथा उप महाप्रबंधक (एच.आर.झएल. एंड डी.) वाई एस जौहरी उपस्थित थे।

मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक (मानव संसाधन) पवन कुमार ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि खेल गतिविधियां व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व क्षमता, अनुशासन एवं सामूहिकता की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। उन्होंने इस आयोजन को आगामी वर्षों में भी निरंतर जारी रखने की अपेक्षा व्यक्त की।

संजीव श्रीवास्तव ने स्वागत उद्बोधन प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'जोश-2026' केवल खेल प्रतियोगिता नहीं, बल्कि संगठनात्मक संस्कृति को सशक्त करने की एक सार्थक पहल है। उन्होंने बताया कि 10 वर्षों के अंतराल के बाद इस प्रतियोगिता का पुनः आयोजन विभाग में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगा।

'जोश-2026' के अंतर्गत प्रतियोगिताओं को दो श्रेणियों प्रशिक्षणार्थी एवं विभागीय श्रेणी में आयोजित किया गया। प्रतियोगिताओं में क्रिकेट, शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शॉटपुट, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 400 मीटर रिले रेस तथा म्यूजिकल चेयर जैसी विभिन्न खेल विधाओं का आयोजन किया गया। प्रतिभागियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अपनी क्षमता, समर्पण एवं खेल कौशल का प्रदर्शन किया। विजयी प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया गया। सम्पूर्ण आयोजन का समन्वयन श्री संजय सिंह द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन महाप्रबंधक (एच.आर.एल. एंड डी.) सौरभ वार्ष्णेय द्वारा प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में सुधाकर यादव, प्रवीण कुमार एवं अजय कुमार तिवारी का विशेष योगदान रहा।

राज्य सरकार का यह तीसरा बजट "संकल्प" थीम पर आधारित : विनय

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई भाजयुमो महामंत्री विनय सेन ने 1.72 लाख करोड़ के राज्य के बजट को छत्तीसगढ़ के आधुनिक विजन का बजट बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रस्तुत यह तीसरा बजट "संकल्प" थीम पर आधारित है। कार्यक्रम का संचालन लक्ष्मी नारायण अग्रवाल द्वारा किया गया। प्रतियोगिताओं के सफल संचालन में सुधाकर यादव, प्रवीण कुमार एवं अजय कुमार तिवारी का विशेष योगदान रहा।

तक सीमित नहीं है,बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह बजट पिछले साल से लगभग 10 प्रतिशत अधिक है। इसमें भाजपा सरकार ने हर वर्ग के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। जनता को राहत देते हुए किसानों को ब्याज मुक्त कर्ज देने और बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट समावेशी विकास, क्षेत्रीय संतुलन, मजबूत आधारभूत संरचना, मानव संसाधन विकास, अंतिम छोर तक सेवाओं की उपलब्धता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी को पूरा करने और छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक सशक्त कदम है।यह बजट ज्ञान और गति का संगम और विकसित छत्तीसगढ़ का आधारस्तम्भ है।बजट में युवाओं के कौशल विकास,स्वरोजगार और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन पर जोर दिया गया है।

श्रमिक की बेटी डिंपल कश्यप अब संस्कार सिटी स्कूल में संवार रही अपना भविष्य

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ में शिक्षा के क्षेत्र में आई क्रांति अब सुदूर अंचलों के गरीब और श्रमिक परिवारों के आंगन तक पहुँचकर उनके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल रही है। शासन की अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के माध्यम से प्रदेश के होनहार विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय शिक्षा दिलाने का संकल्प अब धरातल पर जीवंत होता दिख रहा है। इसी कड़ी में आदिवासी बहुल बस्तर जिले के जगदलपुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम बिलौरी के एक पंजीकृत श्रमिक नंदकिशोर कश्यप की सुपुत्री डिंपल कश्यप ने अपनी मेधा और कड़ी मेहनत के दम पर सफलता का अध्याय लिख दिया है। डिंपल का चयन राज्य की प्रावीण्य सूची (मेरिट लिस्ट) के आधार पर राजनांदगांव के प्रतिष्ठित संस्कार सिटी स्कूल के लिए हुआ है, जो उनके परिवार के लिए किसी सुखद चमत्कार से कम नहीं है। यहां डिंपल कक्षा छठवीं में अध्ययन कर रही है और बारहवीं तक निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेगी।

इस गौरवपूर्ण उपलब्धि की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कमर्कार कल्याण मंडल ने डिंपल की माध्यमिक शिक्षा से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की पूरी पढ़ाई का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली है। इस निःशुल्क और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के प्रावधान ने परिवार के सिर से आर्थिक चिंता का बोझ पूरी तरह हटा दिया है, जिससे अब डिंपल की प्रगति की राह में कोई बाधा नहीं आएगी। अपनी बेटी की इस अभूतपूर्व सफलता पर पिता नंदकिशोर कश्यप भावुक स्वर में कहते हैं कि एक श्रमिक के लिए यह किसी सपने के सच होने जैसा है। वे दिन-रात कड़ी मेहनत ही इसलिए करते हैं ताकि उनके बच्चों का भविष्य उनके अपने संघषर्पूर्ण जीवन से कहीं बेहतर और सुगम हो सके। आज सरकार की इस कल्याणकारी योजना ने उनके उन धुंधले सपनों को हकीकत के पंख दे दिए हैं।

माता-पिता के रूप में कश्यप दंपत्ति आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्हें अब यह अटूट विश्वास हो चला है कि उनकी बेटी का भविष्य न केवल सुरक्षित है, बल्कि वह अपनी अटूट लगन से सफलता के उस आसमान को भी छू सकेगी जिसका उन्होंने कभी केवल कल्पनाओं में विचार किया था। ग्राम बिलौरी-2 से निकलकर एक प्रतिष्ठित स्कूल तक का डिंपल का यह सफर समाज के उस हर वर्ग के लिए प्रेरणा है, जो संसाधनों के अभाव में अपनी प्रतिभा को दबाए बैठे हैं। शासन की यह पहल स्पष्ट संदेश देती है कि यदि बच्चे में प्रतिभा और आगे बढ़ने की ललक हो, तो सरकार की योजनाएं एक मजबूत सेतु बनकर उन्हें सफलता के उच्चतम शिखर तक पहुँचाने में पूरी मदद करती हैं।

खास खबर

राज्यपाल रमेन डेका ने वीर विनायक दामोदर सावरकर को श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

राज्यपाल रमेन डेका ने महान सेनानी, विचारक और क्रांतिकारी विनायक दामोदर सावरकर 'वीर सावरकर' जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने राष्ट्रनिर्माण में उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि वीर सावरकर भारत माता के उन वीर सपूतों में से एक हैं। जिनकी बौद्धिक क्षमता, क्रांतिकारी उत्साह और भारत के भविष्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता अतुलनीय रही। वीर सावरकर जी महज एक क्रांतिकारी से कहीं अधिक थे, वे एक गहन विचारक थे जिनके बौद्धिक योगदान को देश भूल नहीं सकता। इस अवसर पर राज्यपाल के विधिक सलाहकार भीष्म प्रसाद पाण्डेय, उप सचिव सुश्री निधि साहू एवं अधिकारियों-कर्मचारियों ने भी सावरकर जी के छायाचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी।

जेलपारा एनीकट एवं टेंगापाली वितरक के कार्यों के लिए 8.19 करोड़ रुपए स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा रायगढ़ जिले के अंतर्गत केलो नदी पर दो सिंचाई योजनाओं के कार्यों के लिए 8 करोड़ 19 लाख 64 हजार रुपए स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत कार्यों में विकासखण्ड-रायगढ़ अंतर्गत केलो नदी पर जेलपारा एनीकट के जीणीद्धार कार्य के लिए 3 करोड़ 85 लाख 79 हजार रुपए स्वीकृत किए है। प्रस्तावित कार्य से एनीकट का मरम्मत एवं समस्त क्षतिग्रस्त गेट का पुर्ननिर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। विकासखण्ड-पुसौर के अंतर्गत केलो परियोजना के टंगापाली विरतक नहर के कांक्रीट लाईनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 33 लाख 85 हजार रुपए स्वीकृत किए गए है। योजना के कार्यों के पूरा हो जाने पर योजना की रूपांकित सिंचाई क्षेत्र 1151.53 हेक्टेयर में 258.53 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति सहित पूर्ण रूपांकित क्षेत्र में सिंचाई सुविधा होगी।

अटैचमेंट पर सख्ती : गैर-शैक्षणिक कार्य में लगे शिक्षकों को स्कूल लौटने का आदेश

रायपुर। अटैचमेंट लेकर अन्य विभागों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों पर अब सख्ती शुरू हो गई है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ (डीपीआई) ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए गैर-शैक्षणिक कार्यों में संलग्न सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को उनके मूल पदस्थापना स्थल पर लौटने का आदेश दिया है। डीपीआई द्वारा प्रदेश के सभी संयुक्त संचालक, शिक्षा संभाग और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा गया है कि ऐसे शिक्षक और कर्मचारी जो अपनी मूल सेवाएं छोड़कर अन्य कार्यालयों या संस्थाओं में गैर-शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से कायर्मुक्त कर मूल संस्था में उपस्थित होने के निर्देश दिए जाएं। संबंधित अधिकारियों को की गई कार्रवाई से संचालनालय को अवगत कराने को भी कहा गया है।

कलेक्टर और कमिश्नरों को भी निर्देश

डीपीआई ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों और संभागायुक्तों को भी पत्र लिखकर इस आदेश के पालन को सुनिश्चित करने को कहा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य शासन को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि शिक्षक संवर्ग के कर्मचारी गैर-शैक्षणिक कार्यों में संलग्न हैं, जिससे स्कूलों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गैर-शैक्षणिक कार्यों में लगे सभी शिक्षकों का संलग्नीकरण तत्काल समाप्त कर उन्हें उनके मूल विद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए कायर्मुक्त किया जाए।

7 दिन में देनी होगी रिपोर्ट

डीपीआई ने आदेश में यह भी कहा है कि संलग्नीकरण समाप्त किए जाने का प्रमाण पत्र सात दिवस के भीतर संचालक, लोक शिक्षण को अनिवार्य रूप से भेजा जाए। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्रवाई से लंबे समय से चल रहे अटैचमेंट के खेल पर रोक लगने की उम्मीद जताई जा रही है।

नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा

नशे में बस चलाना पड़ा महंगा, बारातियों से भरी प्राइवेट बस जब्त, चालक गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / बालोद

शराब के नशे में बारातियों को लेकर बस चलाना एक प्राइवेट बस चालक को भारी पड़ गया। बालोद यातायात पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए बस को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई के चलते बारातियों को करीब दो घंटे तक थाने के बाहर दूसरी बस का इंतजार करना पड़ा।

मिली जानकारी के अनुसार, बीती रात करीब 7 बजे 20 से अधिक बाराती एक प्राइवेट बस से मानपुर-मोहला जिला के खटगांव-भटगांव से वापस अपने घर अभनपुर के भाटापारा बेलर लौट रहे थे। इसी दौरान झलमला चौक के पास वाहन जांच में बस को रोका गया।

जांच के दौरान बस चालक शराब के नशे में पाया गया। इसके बाद यातायात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बारातियों को बस से नीचे उतारा और बस को जब्त कर सिटी कोतवाली थाना बालोद ले आई। वहीं नशे में पाए गए चालक को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई।

अचानक हुई इस कार्रवाई से बारातियों में अफरा-तफरी मच गई। सभी बाराती थाने के बाहर करीब दो घंटे तक दूसरी बस का इंतजार करते रहे। बाद में बस मालिक द्वारा वैकल्पिक बस भेजे जाने पर बाराती अपने गंतव्य की ओर रवाना हो सके। फिलहाल जब्त की गई प्राइवेट बस को बालोद थाना परिसर में खड़ा कर दिया गया है और यातायात पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रहेगा और यात्रियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

खैरागढ़ पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास की बदहाली, छात्रों ने कलेक्टोरेट पहुंचकर लगाई गुहार

खैरागढ़। पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के छात्र अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर कलेक्टोरेट पहुंचे। छात्रों ने छात्रावास की व्यवस्थाओं को बदहाल बताते हुए प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। छात्रों ने बताया कि वे और उनके साथी लंबे समय से गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। छात्रों का आरोप है कि जब भी वे अपनी परेशानियों को छात्रावास अधीक्षक के सामने रखते हैं, तो उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई समाधान नहीं होता। छात्रों ने बताया कि हाल ही में बोर खराब हो जाने के कारण उन्हें पूरे दिन पानी के लिए भटकना पड़ा। इसके अलावा पाइपलाइन टूटने जैसी समस्याओं और अन्य मेंटेनेंस कार्यों को भी छात्र खुद ही करने को मजबूर हैं। छात्रों का यह भी कहना है कि अधीक्षक महीने में केवल एक-दो बार ही छात्रावास आते हैं और वह भी महज 10 से 30 मिनट रुककर कागजी कार्य निपटाकर चले जाते हैं। छात्रों के अनुसार अधीक्षक न तो उनका हाल-चाल पूछते हैं और न ही समस्याओं को गंभीरता से लेते हैं। पूछने पर कलेक्टर कार्यालय में व्यस्त रहने का हवाला दे दिया जाता है। वतर्मान में छात्रावास का संचालन रसोइए और नाइट ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों के भरोसे ही चल रहा है।

किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाला बजट : शशिकांत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (माकर्फेड) के प्राधिकारी श्री शशिकांत द्विवेदी ने वित मंत्री ओपी चौधरी द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तुत 1,72,000 करोड़ रूपए का बजट को किसानों, महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने वाली बजट बताया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हमारा गांव, हमारी सरकार की अवधारणा को साकार करने हेतु ग्रामीण विकास, कृषि उन्नयन एवं महिला सशक्तिकरण पर विशेष प्रावधान किए गए हैं। बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं शामिल की गई हैं, जिनका लाभ प्रदेश की हजारों महिलाओं को मिलेगा। श्री द्विवेदी ने बताया कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से कृषि उन्नति योजना के साथ ही कृषि, सिंचाई एवं आजीविका से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है।

किसानों को कर्ज के बोझ से राहत देने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से 300 करोड़ रूपए की ब्याजमुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण योजना जारी रखने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत किसानों को बिना ब्याज के फसली ऋण उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे खाद-बीज एवं कृषि उपकरणों की व्यवस्था सुगमता से हो सकेगी।

फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी एवं कपास जैसी फसलों को विशेष योजना में शामिल किया गया है। इसके लिए 10,000 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही धान खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने हेतु 6,000 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई है। यह बजट प्रदेश के किसानों, महिलाओं और युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं प्रोत्साहन की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

तीन परिवारों को 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर

कवर्धा। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत तीन विपत्तिग्रस्त परिवारों को चार-चार लाख रूपए की मान से 12 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृत दी है। इसके तहत ग्राम दरिया निवासी साजन मेरावी की तालाब में डूबने से मृत्यु हो जाने पर विपत्तिग्रस्त उनके पति संपत सिंह को, ग्राम आमानारा निवासी टीकोबाई की नाला में डूबने से मृत्यु हो जाने पर विपत्तिग्रस्त उनके पुत्र कारेलाल को और ग्राम कुल्हीडोंगरी निवासी किरण परस्ते की सर्प काटने से मृत्यु हो जाने पर विपत्तिग्रस्त उनके पिता राजकुमार परस्ते को राजस्व पुस्तक परिपत्र छह-चार के तहत चार-चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी गई है।

स्व सहायता समूह की महिलाएं कर रही है प्राकृतिक गुलाल का निर्माण

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

रंगों के त्योहार होली को स्वसहायता समूह की महिलाएं इस बार और खास बना रही है। होली के त्योहार को प्राकृतिक रंगों से मनाने के लिए महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही है। गरियाबंद जिले के ग्राम सढ़ौली की राखी महिला ग्राम संगठन की 10 सक्रिय महिलाएँ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत हर्बल गुलाल का निर्माण कर आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की मिसाल पेश कर रही हैं। समूह की महिलाएं पलाश से पीला, चुंकदर से लाल और पालक के पत्तों से हरा रंग निकालकर मक्के की सूखी डंठल से प्राप्त अरारोट पाउडर में मिलाकर प्राकृतिक गुलाल का निर्माण कर रही है। इसमें हानिकारक रसायनिक तत्वों का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाता।

जिससे हर्बल गुलाल त्वचा एवं सेहत के लिए सुरक्षित रहता है। राखी महिला ग्राम संगठन की ये महिलाएँ न केवल होली के त्योहार को प्राकृतिक और सुरक्षित बना रही हैं, बल्कि अपनी आजीविका को भी मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की नई कहानी लिख रही हैं। यह पहल प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। कलेक्टर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने इन महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आज महिलाएं स्वरोजगार सृजित कर आत्मनिर्भर बन रही है और समाज में अपनी अलग पहचान बना रही है। पीआरपी मीना साहू ने बताया कि पिछले वर्ष भी बिहान समुह के दीदियों द्वारा कुल 30 हजार रूपये से अधिक की बिक्री कर लगभग 10 हजार रूपये से अधिक की शुद्ध मुनाफा अर्जित की थी।

समूह की महिलाओं से चर्चा के फलस्वरूप पारंपरिक तरीकों से बनाए गए प्राकृतिक गुलाल से न केवल सेहत स्वस्थ रहेगा, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अनुकूल रहेगा। साथ ही महिलाओं के लिए आमदनी का नया स्रोत भी बन रहा है। पिछले वर्ष हर्बल गुलाल की मांग अधिक रही, जिसे देखते हुए इस बार महिलाओं ने रंग बनाना शुरू कर दिया है। महिलाओं ने बताया कि गुलाल बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह प्राकृतिक है। इसे तैयार करने में फूलों और पत्तियों का उपयोग किया जाता है, जिससे यह त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। विभिन्न रंग बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता है गुलाबी रंग के लिए चुकंदर और गुलाब की पंखुड़ियां, पीला रंग के लिए हल्दी और गेंदे के फूल, हरा रंग के लिए पालक व मेंहदी के पत्ते, नीला रंग के लिए अपराजिता के फूल और लाल रंग के लिए टेसू के फूलों का इस्तेमाल कर रही है।

हर्बल गुलाल से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान से जुड़ी कबीरधाम जिले की महिला स्व-सहायता समूह महिला सशक्तीकरण की दिशा में आगे बढ़ रही है। जनपद पंचायत बोडला के ग्राम राजा नवागांव की जय गंगा मैया स्व-सहायता समूह से जुड़ी दीदियों ने रंगोत्सव त्योहार होली के लिए हर्बल गुलाल का निर्माण किया है। महिला समूह ने हर्बल गुलाल के व्यवसाय से जुड़कर आजीविका के नए रास्ते खोले है। इस गतिविधि में 10 महिलाओं की प्रत्यक्ष भागीदारी है, जो उनके आय का अच्छा स्रोत है। लाल, गुलाबी, पीले सहित अन्य रंगों और प्रकृति खुशबू से भरपूर हर्बल गुलाल बाजार में आने के लिए उपलब्ध है। कलेक्टर कबीरधाम गोपाल वर्मा ने बताया कि प्रत्येक वर्ष होली के अवसर पर जिले की विभिन्न महिला समूह द्वारा हर्बल गुलाल का निर्माण किया जाता है। कलेक्टोरेट, सभी जनपद पंचायत कार्यालय एवं अन्य स्थानों पर उनके द्वारा स्टॉल लगाकर हर्बल गुलाल की बिक्री की जाती है। समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए गुलाल पूरी तरह से प्राकृतिक होने के साथ-साथ बाजार में मिलने वाले अन्य रंगों की तुलना में सस्ता होता है। हर्बल गुलाल की पैकेजिंग बहुत आकर्षक है और यह उपहार देने के भी बहुत अच्छा है। हर्बल गुलाल अनेक रंगो के साथ अलग-अलग मात्रा में पैकेजिंग सहित उपलब्ध है। गतवर्ष भी हमने देखा है कि समूह की दीदियों द्वारा बनाए गए हर्बल गुलाब को क्षेत्रवासियों ने बहुत पसंद किया है और इस व्यवसाय से जुड़कर हमारी ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है।

उपलब्धि — किसान मुकेश कमा रहे हैं एक पेड़ से 3 हजार रुपए वार्षिक आय

एक एकड़ में सवा लाख रुपए का मुनाफा देने वाला पाम ऑयल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पाम ऑयल उत्पादन में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने, आयात पर निर्भरता कम करने तथा किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से संचालित नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल - ऑयल पाम योजना महासमुंद जिले के किसानों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना के माध्यम से किसान अपनी बंजर भूमि को उपजाऊ बनाकर लाखों रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं और अन्य किसानों के लिए प्रेरणास्रोत बन रहे हैं। जिले में इस योजना तहत लगभग 400 किसान लगभग 450 हेक्टेयर क्षेत्र में ऑयल पाम की खेती कर रहे हैं।

इसी क्रम में सरायपाली भलेसर गांव के उन्नत किसान मुकेश चंद्राकर, जिन्होंने वर्षो से बंजर पड़ी अपनी 33 एकड़ भूमि पर वर्ष 2016 में ऑयल पाम की खेती प्रारंभ की। वे शासन की योजना से पाम खेती के लिए प्रेरित हुए और अपनी पूरी भूमि पर लगभग 1900 पौधे लगाए। योजना के अंतर्गत उन्हें पौध प्रदाय, फेंसिंग, रखरखाव तथा ड्रिप सिंचाई जैसी सुविधाएं अनुदान पर मिला। तीन से चार वर्षों में उत्पादन प्रारंभ हुआ, जो लगभग 35 वर्षों तक लगातार फल देता रहेगा। वतर्मान में श्री चंद्राकर एक पौधे से औसतन 3000 रुपये वार्षिक आय अर्जित कर रहे हैं। प्रति एकड़ लगभग 1 लाख 25 हजार रुपये की आय प्राप्त हो रही है।

इसके अतिरिक्त, उन्होंने पाम पौधों के बीच अंतरवर्तीय फसल के रूप में पहले केले की खेती की, जिससे उन्हें लगभग डेढ़ लाख रुपए का लाभ हुआ। वतर्मान में वे कोको की खेती कर निजी कंपनियों को उत्पाद विक्रय कर रहे हैं, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय प्राप्त हो रही है। श्री चंद्राकर बताते है कि कम पानी, कम खाद एवं कम कीटनाशक में अधिक उत्पादन और बेहतर लाभ मिलने के कारण किसानों को पाम की खेती अपनानी चाहिए। श्री चंद्राकर न केवल आत्मनिर्भर बने हैं, बल्कि अपने खेतों में दो दर्जन से अधिक लोगों को स्थायी रोजगार भी प्रदान कर रहे हैं। स्थानीय मजदूरों के अनुसार, पहले रोजगार के लिए भटकना पड़ता था, जबकि अब वर्षभर यहीं नियमित कार्य उपलब्ध हो रहा है।

सहायक संचालक उद्यानिकी विभाग श्रीमती पायल साव ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पाम ऑयल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इसके अंतर्गत किसानों को अनुदान, तकनीकी मार्गदर्शन एवं विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें उत्पादन एवं विक्रय में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। जिले में पाम ऑयल की खेती को बढ़ावा देने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। यहां किसानों के रूझान और भूमि की प्रकार को देखते हुए कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने भी किसानों से अधिकाधिक संख्या में पाम की खेती करने अपील की है।

गौरतलब है कि खाद्य पदार्थो, साबुन, शैम्पू, सौंदर्य प्रसाधन तथा औषधि निर्माण में इसका व्यापक उपयोग होता है। ऐसे में जिले में कम लागत, कम श्रम, कम पानी एवं अधिक आय देने वाली पाम खेती किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। यह पहल फसल चक्र परिवर्तन को बढ़ावा देने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में एक सशक्त कदम सिद्ध हो रही है।

श्रमिक सम्मेलन : जिले के 7930 श्रमिक हुए लाभान्वित

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के निर्देशानुसार श्रमिक सम्मेलन-2026 का आयोजन उत्तर बस्तर कांकेर जिले के सामुदायिक भवन अंतागढ़ में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में लोकसभा क्षेत्र कांकेर के सांसद भोजराज नाग उपस्थित थे तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता नगर पंचायत अंतागढ़ के अध्यक्ष राधेलाल नाग द्वारा की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कमर्कार कल्याण मंडल एवं छत्तीसगढ़ असंगठित कमर्कार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल के अन्तर्गत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से जिले के श्रमिक व उनके परिवार के सदस्यों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डी.बी.टी.) के माध्यम से राशि हस्तांतरित कर लाभान्वित किया गया।

श्रमिक सम्मेलन में उपस्थित सांसद श्री नाग ने सभी उपस्थित श्रमिकों और उनके परिजनों को विभाग में संचालित योजनाओं का लाभ लेने की अपील की। साथ ही योजनाओं के संबंध में जागरूक होने की बात कही। नगर पंचायत अध्यक्ष श्री नाग ने भी श्रमिकों को संबोधित करते हुए शासन द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों का अधिक से अधिक लाभ उठाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों के द्वारा लाभार्थी श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के तहत चेक वितरित किए गए।

श्रम पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि श्रमिक सम्मेलन में जिले के कुल 7930 श्रमिकों को कुल 02 करोड़ 29 लाख 17 हजार 100 रूपये से लाभान्वित किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कमर्कार कल्याण मंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना में 101 हितग्राहियों को 20 लाख 20 हजार रूपए, मिनीमाता महतारी जतन योजनांतर्गत 89 महिला हितग्राहियों को 17 लाख 80 हजार रूपए, मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा सहायता योजना में 50 हितग्राहियों को 02 लाख 59 हजार 100 रूपये, मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजनांतर्गत 28 हितग्राहियों को 05 लाख 60 हजार रूपये, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत 19 श्रमिकों के उत्तराधिकारियों को 01 करोड़ 90 लाख रूपये एवं मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजनांतर्गत 04 श्रमिकों को 04 लाख रूपए, दीदी ई-रिक्शा सहायता योजनांतर्गत 01 महिला हितग्राही को 01 लाख रूपये डी.बी.टी. के माध्यम से प्रदाय किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधिगण एवं अतिथिगण तथा श्रम पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में श्रमिकगण मौजूद थे।

संपादकीय

यकीन हो गया है कि सरेंडर नहीं किए तो मारे जाएंगे

चाहे छत्तीसगढ़ के नक्सली हों या आसपास के राज्य के नक्सली हों या उनके सबसे बड़े नेता उनको अमित शाह की नकसलियों की सफाया नीति पर प्रभावी अमल से यकीन हो गया है कि वह सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे ।यही वजह है कि पिछले एक दो साल में कई बड़े नेताओं ने सरेंडर किया ताकि वह जिंदा रहें ।जिन बड़े नेताओं ने सरेंडर नहीं किया वह सुरक्षा बलों के हाथों मारे गए हैं । बड़े बड़े नेताओं के मारे जाने के कारण ही नक्सलियों में पहली बार मारे जाने का खौफ पैदा हुआ है । जब बड़े नेता मारे गए तो निचले स्तर के नक्सली नेताओं को एहसास हुआ कि जब बड़े नेता अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी रक्षा क्या करेंगे और मारे जाने के खौफ से ही जितने नक्सली मारे गए हैं, उससे ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है । अमित शाह की यह बड़ी सफलता है कि पहले किसी क्षेत्र में नक्सलियों का खौफ हुआ करता था आज दो साल में स्थिति यह हो गई है कि क्षेत्र के नक्सलियों में मारे जाने का खौफ है ।

अमित शाह ने नक्सलियों में मारे जाने का जो खौफ पैदा किया है, वह इससे पहले किसी राज्य या देश के किसी गृहमंत्री ने पैदा नहीं किया था । राज्यों के कितने ही गृहमंत्री आए गए,देश के कितने ही गृहमंत्री आए गए लेकिन कोई नक्सलियों में मारे जाने का खौफ पैदा नहीं कर सका था ।वे सब मानते ही नहीं थे कि नक्सलियों में मारे जाने का खौफ पैदा किया जा सकता है इसलिए वह ऐसा कोई तरीका सोच भी नहीं पाए । अमित शाह से तय कर लिया कि इतने समय में नक्सलियो का सफाया करना है तो योजना बनाई कि कैसे नक्सलियों का उनके गढ़ में घुसकर मारा जा सकता है । सुरक्षा बलों की संख्या को नक्सलियों से ज्यादा किया । इससे सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को घेर कर मारना शुरू किया । कई बड़े नेताओं को घेर कर मार गिराया । इससे एक ओर तो सुरक्षा बलों में भरोसा पैदा हुआ कि हम नक्सलियों का मार सकते हैं और नक्सलियों में डर पैदा हुआ कि अब उनका कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है और वह कभी भी मारे जा सकते हैं ।

अगर अमित शाह ने नक्सलियों में यह खौफ पैदा न किया होता कि वह सरेंडर नहीं करेंगे तो कभी भी, कहीं भी मारे जा सकते हैं, नक्सलियों की संख्या बस्तर सहित कई राज्यों में कम नही हुई होती ।नक्सलियों की संख्या बस्तर में कम होने के साथ ही आसपास के राज्यों में भी कम होती गई है तो छत्तीसगढ़ सहित भाजपा शासित राज्यो में नक्सलियों के मारे जाने के कारण और सबसे ज्यादा सरेंडर करने के कारण कम हो गई है ।नक्सलियों की संख्या कम होने के कारण बड़े नेताओं के सामने भी स्थिति यह हो गई थी कि वह कुछ करने की स्थिति में नहीं रह गए थे । क्योंकि कुछ करने के लिए आदमियों की जरूरत होती है । वह न पहले जैसे हमला कर पा रहे थे, न नए सदस्य भर्ती कर पा रहे थे, न कहीं ट्रेनिंग दे पा रहे थे, उनके सुरक्षित ठिकाने नष्ट कर दिए गए तो बड़े नेताओं को लगा कि जान तो उनकी अब किस राज्य में बच नहीं सकती उनके सामने भी सरेंडर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है. यही वजह है कि सबसे बड़े नक्सल नेता देवजी को भी सरेंडर करना पड़ा है ।

बसवा राजु,माडंवी हिड़मा,चलपति,प्रयाग मांझी,मोडेम बालाकृष्णा,रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा,सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा, गणेश उइके,जगदीश सुधाकर आदि सरेंडर नहीं करने के कारण मारे जा चुके है,देवजी के सरेंडर करने के बाद अब माना जा रहा हैकि मिसीर बेसरा,व गणेश सहित गिनती के लोग ही बचे हैं । इससे नक्सली संगठन अब नाम को ही बचा है । जहां कहीं नक्सली गिनती के बचे हैं, वह भी सरकार को पत्र लिखकर कह रहे हैं कि वह सरेंडर करना चाहते हैं । बीबीएम के बचे हुए १५ सदस्यों ने गृहमंत्री विजय शर्मा को पत्र लिखकर बताया है कि उन्हें सुरक्षा की गारंटी दी जाए तो वह सरेंडर करना चाहते हैं ।अगर यह सरेंडर होता है तो महासमुंद जिला नक्सलमुक्त घोषित किया जा सकता है ।राजनांदगांव रेंज में महाराष्ट्र,मप्र,छत्तीसगढ़ जोन(एमएमसी जोन) के माओवाद प्रभावित जिले दिसंबर में ही नक्सलमुक्त हो गए हैं ।इसमें खैरागढ़,छुईखदान,गंडई,राजनांदगाव, कबीरधाम जिला शामिल हैं ।

नक्सलियों के मारे जाने व सरेंडर किए जाने से उम्मीद की जा सकती है कि जहां भी नक्सली बचें है, उन तक बड़े नेताओं के सरेंडर करने से यह संदेश तो पहुंच रहा है कि मारे जाने से अच्छा है कि सरेंडर करना क्योंकि नक्सली संगठन बचा भी रहता है तो आज वह ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह कहीं कुछ कर सके क्योंकि उसके पास न पैसा है और न ही पहले जैसा संगठन । जो नक्सली नेता सरेंडर करता है तो वह यही कहता है कि बदलते सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हालात मे सशस्त्र संघर्ष जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया है वह अब संविधान के दायरे में रहकर काम करना चाहते हैं । जब अमित शाह ने नक्सलवाद के खात्मे की तारीख बताई थी को बहुत कम लोगों को लगता था कि ऐसा हो पाएगा लेकिन अब जब इस तारीख को कुछ दिन बचे हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि २६ मार्च के पहले ही नक्सलवाद का खात्मा मोटे तौर हो जाएगा ।जो अब तक असंभव माना जाता था वह अब संभव लगता है लोगों को ।

वैश्विक अर्थव्यवस्था में अविश्वास बढ़ रहा है

अजीत द्विवेदी

चौतरफा अविश्वास बढ़ रहा है । नियम आधारित पुरानी विश्व व्यवस्था बिखर गई है । दुनिया के किसी भी देश को दूसरे देश पर या देशों के किसी भी समूह को दूसरे समूह पर भरोसा नहीं रह गया है । जब अमेरिका और यूरोप के बीच अविश्वास बढ़ गया तो बाकी देशों के बारे में क्या कहा जाए! इसी तरह वैश्विक अर्थव्यवस्था में अविश्वास बढ़ रहा है । दुनिया की अर्थव्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निवेश और उसके बाजार में आए उछाल से चलती दिख रही है । इसने सॉफ्टवेयर और आईटी आधारित सेवाओं के उद्योग को लगभग ध्वस्त कर दिया है ।

जब से एआई कंपनी एंथ्रोपिक की ओर से कहा गया कि उसके ऑटोमेटेड ऑफिस सूट से सॉफ्टवेयर और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जरुरत ही खत्म हो जाएगी तब से आईटी कंपनियों की हालत खराब है । माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ ने भी कहा है कि अगले डेढ़ से दो साल में सारे व्हाइट कॉलर जॉब्स एआई के जरिए ऑटोमेटेड हो जाएंगे । हालांकि इसके बावजूद चिप बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी एनवीडिया के निवेशक अपने पैसे निकाल रहे हैं । सॉफ्टबैंक से लेकर पीटर थील तक ने पैसे निकाले हैं तो यह भी खबर है कि कंपनी के सीईओ से लेकर दूसरे अहम लोग भी अपने शेयर बेच रहे हैं । यह अविश्वास पूरी अर्थव्यवस्था को अपने चपेट में ले सकता है ।

वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक अविश्वास के माहौल में सबसे चिंता की स्थिति भारत में दिख रही है, जहां राजनीतिक और सामाजिक विभाजन दिन प्रतिदिन गहरा होता जा रहा है । भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ कहने की जरुरत नहीं है । यह उपभोग आधारित है तो डेढ़ सौ करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था चलती ही रहेगी और जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से बढ़ती रहेगी । लेकिन सामाजिक और राजनीतिक विभाजन, अविश्वास देश के सामने बड़ा खतरा बन कर आया है ।

देश की राजनीति में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही थी कि सत्तारूढ़ और विपक्षी पार्टियों के बीच एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव हो । अब पार्टियों के बीच निजी दुश्मनी हो गई है । संसद और राज्यों की विधानसभाओं में पार्टियों के नेता एक दूसरे से दुआ सलाम करने से घबरा रहे हैं कि कहीं उनके शीर्ष नेता ने देख लिया या पता चल गया तो उसके नंबर कट जाएंगे ।

अगर पहले सामाजिक विभाजन की बात करें तो इतने गहरे विभाजन की शुरुआत 80 बनाम 20 की राजनीति से हुई थी और यूजीसी के नियमों से अंतिम मुकाम तक पहुंची है । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भले 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की बात कही लेकिन उनकी पार्टी की नीतियों और नेताओं के बयानों से यह संदेश गया कि भाजपा को 20 फीसदी अल्पसंख्यकों, जिनमें मुस्लिम, सिख और ईसाई तीनों शामिल हैं उनके वोट नहीं चाहिए । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो खुल कर 80 और 20 की बात कही । उन्होंने बंटोंगे तो कटोगे का नारा दिया । प्रधानमंत्री ने भले ऐसा कोई नारा नहीं दिया लेकिन जब भाजपा ने लोकसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया और एक भी मुस्लिम को मंत्री नहीं बनाया गया तो बिना कहे यह सिद्धांत स्थापित हुआ ।

मुसलमानों को अलग थलग करने की जो राजनीति शुरू हुई थी उसमें राज्यवार दूसरी चीजें जुड़ती गईं । बिहार और उत्तर प्रदेश में मुस्लिम के साथ साथ यादव को अलग थलग किया गया । हरियाणा में जाट को, महाराष्ट्र में मराठों को, झारखंड में आदिवासियों को अलग थलग किया गया । कहीं गैर यादव पिछड़ी व अन्य जातियों का समीकरण बनाया गया तो कहीं गैर मराठा तो कहीं गैर आदिवासी का समीकरण बनाया गया । अब इस विभाजनकारी राजनीति का अगला मुकाम सामान्य जातियों को अलग थलग करने का है । उच्च शिक्षण संस्थानों में भेदभाव खत्म करने के लिए यूजीसी की ओर से जो नियम लाए गए हैं, जिनको भेदभावकारी बता कर सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया है, वो इसी प्रयोग का हिस्सा हैं ।

भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसकी सरकार के मंत्री अब खुल कर कह रहे हैं कि वे देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के लिए काम कर रहे हैं । सरकार की पूरी स्कीम ऑफ थिंग्स में से सामान्य जातियों को बाहर कर दिया गया है । इससे सामाजिक स्तर पर इतना अविश्वास बढ़ा है कि जाति पूछ कर यूनिवर्सिटी कैम्पस में छात्रों पर हमले हो रहे हैं । दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैम्पस में एक ब्राह्मण पत्रकार की जाति पूछ कर उसके ऊपर हमला किया गया । विपक्ष खास कर राहुल गांधी की बहुजन राजनीति से घबरा कर भाजपा ने यह प्रयोग किया । उसको लग रहा है कि सामान्य जातियां उसको बाई डिफॉल्ट वोट देंगी । लेकिन अब यह वोट का मामला नहीं रह गया है ।

जहां तक गहरे राजनीतिक विभाजन की बात है तो इसकी शुरुआत 'कांग्रेस मुक्त भारत' के नारे से हुई थी । प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने यह नारा दिया था । उसके बाद से भाजपा, उसकी सरकार, उसका पूरा इकोसिस्टम और मीडिया व सोशल मीडिया का पूरा तंत्र इस काम में लग गया कि किस तरह से कांग्रेस शासन की पूरी विरासत को मिटाया जाए, कैसे उसके नेताओं की साख खराब की जाए, कैसे उसे कमजोर किया जाए और कैसे उसे चुनाव हराया जाए ।

इसके बाद भाजपा ने यह प्रचार शुरू किया कि सिर्फ वही एक अच्छी पार्टी है बाकी पार्टियां भ्रष्ट, परिवारवादी और राष्ट्रविरोधी हैं । चुनाव के समय पहले भी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाती थीं । लेकिन भाजपा ने इसे रोजमर्रा का काम बना दिया । 24 घंटे और 365 दिन भाजपा की मशीनरी इस काम में लग गई । पहले तो पार्टियां, नेता और आम लोग भी इसे आश्चर्य की नजर से देखते रहे लेकिन फिर यह मुख्यधारा का राजनीतिक काम बन गया कि एक दूसरे के खिलाफ निरंतर दुष्प्रचार चले ।

अब विपक्षी पार्टियों की सरकारों के नीतिगत फैसलों और नेताओं के निजी चरित्र को लेकर लगातार आलोचना चलती रहती है । लगातार 12 साल प्रधानमंत्री रहने के बाद भी नरेंद्र मोदी कांग्रेस की पहले की सरकारों और नेताओं की कमियां बता कर वोट मांगते हैं । संसद में खड़े होकर भाजपा के सांसद कांग्रेस के पुराने नेताओं और पूर्व प्रधानमंत्रियों को 'गद्दार' और 'अय्याश' बोलते हैं । विपक्ष के मौजूदा नेतृत्व को 'पप्पूइ', 'टुकड़े टुकड़े गैंग', 'देश विरोधी', 'सनातन विरोधी', 'टोंटी चोर', 'चारा चोर'इ आदि कहा जाता है । जवाब में दूसरी तरफ से भी सत्तापक्ष के नेताओं के लिए इसी तरह के विशेषणों का प्रयोग होने लगा है ।

'तड़ीपार' और 'चौकीदार चोर है' से शुरू हुआ प्रचार 'कॉरपोरेट के नौकर', 'देश बेचने वाले' और 'ट्रंप के गुलामइ तक पहुंच गया है । ऐसा नहीं है कि नेता इसे राजनीतिक बयानबाजी भर मान रहे हैं । वे इसे सच मानते हैं और उनके निजी संबंध भी इसी से निर्धारित हो रहे हैं । चूंकि सभी पार्टियों के नेता खास कर भाजपा में ज्यादातर नेता बिना राजनीतिक आधार वाले हैं इसलिए वे अपने पार्टी नेतृत्व की ओर से कही गई बात को ब्राह्म वाक्य मान कर दोहराते रहते हैं । सभी नेताओं का एकमात्र काम अपने नेतृत्व को खुश करना हो गया है । इसके लिए वे विरोधी नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलते रहते हैं । उनके बीच इस बात का कंपीटिशन है कि विरोधी नेता के लिए कौन ज्यादा अपमानजनक बात कह सकता है । अपने विरोधी नेताओं के प्रति अपमान का भाव ही भारतीय राजनीति की पहचान बन गई है ।

भारत को बांग्लादेश के साथ बेहतर समन्वय की जरुरत

बांग्लादेश के साथ भारत की कूटनीति का तीसरा पहलू क्षेत्रीय भू राजनीति से जुड़ा है । बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले की नीति का मुख्य केंद्र रहा है । कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन, ऊर्जा सहयोग, जल बंटवारा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की परस्पर निर्भरता गहरी है ।

शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भारत की विदेश नीति पिछले कुछ दशकों में पूरी तरह से विफल हो गई थी । लगभग सभी पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंधों में तनाव आ गया था । अब भारत ने नए सिरे से संबंध सुधार के प्रयास शुरू किए हैं । बांग्लादेश के नव निर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान के शपथ समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए । वे अपने साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिी लेकर गए थे । प्रधानमंत्री ने उनको भारत आने का न्योता दिया है । यह सिर्फ औपचारिक शिष्टाचार नहीं है, बल्कि यह एक सुविचारित कूटनीतिक पहल भी है । यह पहल दोपक्षीय संबंधों की निरंतरता और उच्च स्तरीय राजनीतिक विश्वास को दिखाता है । दूसरी ओर इसी यात्रा में भारत के विदेश सचिव का बांग्लादेश के प्रमुख विपक्षी नेता और जमात ए इस्लामी के प्रमुख शफीकुर्रहमान से मिलना इस बात का संकेत है कि भारत अपनी नीति को बहुस्तरीय और दीघर्कालिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ा रहा है ।

भारत की एक बहुत अच्छी कूटनीतिक पहल यह रही कि किसी केंद्रीय मंत्री को भेजने की बजाय लोकसभा के स्पीकर को शपथ समारोह में भेज गया । यह दो देशों के संबंधों की भावना को रेखांकित करता है । स्पीकर का पद दलीय राजनीति से ऊपर माना जाता है, इसलिए यह संदेश गया कि भारत की प्रतिबद्धता सिर्फ किसी एक दल या सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि वह संस्थागत संबंधों को महत्व देता है । प्रधानमंत्री का पत्र और भारत आने का निमंत्रण इस बात का संकेत है कि नई सरकार के साथ संवाद को जल्दी से जल्दी और सकारात्मक दिशा में ले जाने की भारत की मंशा है । दूसरी रणनीतिक पहल विदेश सचिव विक्रम मिस्री की बांग्लादेश के विपक्षी नेता से मुलाकात है । शफीकुर्रहमान, बांग्लादेश की कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी के प्रमुख हैं । जमात को पहली बार बांग्लादेश की तीन सौ सदस्यों की संसद में करीब 70 सदस्यों का प्रतिनिधित्व मिला है । यह एक तरह से उसकी राजनीतिक वैधता है । उनसे मुलाकात कर भारत ने यह स्पष्ट किया कि वह केवल सत्तारूढ़ दल पर निर्भर रहकर अपनी विदेश नीति नहीं गढ़ता, बल्कि संभावित सत्ता परिवर्तन की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखता है । हालांकि बांग्लादेश में तारिक रहमान की पार्टी बीएनपी को जबरदस्त जनादेश मिला है लेकिन बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा का मसला वहां के समाज से जुड़ा है और उसे सुनिश्चित करने के लिए जमात के नेता के साथ भारत के संबंधों की बेहतरी भी जरूरी है ।

बांग्लादेश के साथ भारत की कूटनीति का तीसरा पहलू क्षेत्रीय भू राजनीति से जुड़ा है । बांग्लादेश भारत की पड़ोसी पहले की नीति का मुख्य केंद्र रहा है । कनेक्टिविटी, सीमा प्रबंधन, ऊर्जा सहयोग, जल बंटवारा और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर दोनों देशों की परस्पर निर्भरता गहरी है । हालांकि अभी भारत गंगा जल संधि या ट्रांस शिपमेंट पर लगाई गई रोक को लेकर कुछ नहीं कह रहा है और न शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपने की बात हो रही है । लेकिन आने वाले दिनों में ये मुद्दे उठेंगे । इन मुद्दों पर सद्भावपूर्ण तरीके से चर्चा हो यह भारत ने अपनी कूटनीतिक पहल से सुनिश्चित किया है । सीमा प्रबंधन और घुसपैठ रोकने में भी भारत को बांग्लादेश के साथ बेहतर समन्वय की जरुरत होगी ।

पाणिनि से एआई स्टैक तक: दिल्ली का एआई गौरव और राष्ट्रीय क्षमता का लक्ष्य

हरदीप एस पुरी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री

जब पाणिनि ने बोली जाने वाली भाषा की अव्यवस्था को एक संक्षिप्त, गणनीय व्याकरण में परिवर्तित किया, तो उन्होंने एक बात साबित की, जो आज भी प्रासंगिक है : बुद्धिमत्ता सबसे शक्तिशाली तब होती है, जब इसे संरचना के रूप में व्यक्त किया जाता है । नालंदा इस सहज प्रवृत्ति को संस्थानों तक ले गया और बहस करने, संरक्षित करने और ज्ञान को सीमाओं के पार प्रसार करने के तरीके विकसित किए । भारत एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की मेजबानी करने का भारत का निर्णय उसी सभ्यतागत भावना से प्रेरित है, क्योंकि तकनीक में अगली छलांग उन प्रणालियों के बारे में है, जो सीख सकती हैं, तर्क कर सकती हैं और बड़े पैमाने पर कार्य कर सकती हैं और दुनिया ऐसे भविष्य के बारे में सोच नहीं सकती, जिसमें केवल कुछ देश यह तय करें कि ये प्रणालियाँ कैसे बनाई जाएँगी ।

पिछले सप्ताह भारत मण्डपम में आयोजित यह शिखर सम्मेलन, एक वैश्विक दक्षिण राष्ट्र द्वारा आयोजित पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन था और किसी भी पूर्व आयोजन में इस स्तर की भागीदारी नहीं देखी गयी: 20 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष, 60 मंत्री, 100 से अधिक देशों के 500 से अधिक एआई दिग्गज और विषय-आधारित दस पवेलियनों में 300 प्रदर्शक । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत अपनी स्वयं की एक संगठनात्मक सोच प्रस्तुत कर रहा है: डेटा पर संप्रभुता, डिजाइन के अनुसार समावेश और स्वाभाविक जवाबदेही । देश वैश्विक पूंजी को इन शर्तों पर यहाँ निवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहा है ।

प्रधानमंत्री के एम.ए.एन.ए.वी विजन में इस विचार की स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है: नैतिक पाबंदी, जवाबदेह शासन, डेटा पर संप्रभुता, ताकि ज्ञान के कच्चा माल का उस रूप में निष्कर्षण न किया जाए जैसे कभी वस्तुओं का किया जाता था; व्यापक पहुंच, ताकि लाभ मध्य प्रदेश के किसान तक उतने ही निश्चित रूप से पहुंचे, जितना बेंगलुरु के इंजीनियर तक और कानूनी वैधता, ताकि हर प्रयुक्त प्रणाली लोकतांत्रिक निरीक्षण के प्रति जवाबदेह बनी रहे । उनकी अवधारणा एआई को खुला आकाश देने की है, जबकि नियंत्रण मानव हाथों में रखा जाना चाहिए । यह अवधारणा एक ऐसी रेखा खींचती है, जिसे कई उन्नत अर्थव्यवस्थाएं खींचने में हिचकिचा रही हैं ।

अब इन सिद्धांतों का बहुपक्षीय महत्व है, जो शिखर सम्मेलन में अपनाई गई दिल्ली घोषणा के माध्यम से सामने आया, और इसे पहले से ही वैश्विक दक्षिण से आने वाली पहली प्रमुख एआई शासन रूपरेखा कहा जा रहा है । इस घोषणा की दृष्टि विकास-उन्मुख है, जिसका केंद्र तकनीकी-कानूनी दृष्टिकोण है और जो कठोर अनुपालन की तुलना में लचीली पाबंदियों को प्राथमिकता देता है । यह वैश्विक सहयोग को तीन स्तंभों पर व्यवस्थित करता है: लोग, पृथ्वी और प्रगति । भारतजेन जैसा जनसंख्या के पैमाने पर आधारित समाधान, जो 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है और उस वास्तविकता को संबोधित करता है कि दुनिया का अधिकांश भाग अंग्रेजी में काम नहीं करता । भारत के अपने सब्सिडी वाले जीपीयू एक्सेस (?65 प्रति घंटा) पर आधारित एक प्रस्तावित वैश्विक कंप्यूट बैंक प्रवेश बाधाओं को हर जगह कम करता है । घोषणा में डेटा संप्रभुता पर जोर दिया गया है, जो सीधे एआई निष्कर्षणवाद को चुनौती देता है: एक पैटर्न, जिसमें विकासशील देशों से डेटा संग्रहित किया जाता है ताकि मॉडल को प्रशिक्षित किया जा सके । बाद में इन देशों को इसी मॉडल के लिए भुगतान करना पड़ता है ।

पिछले दशक के कार्यान्वयन ने इस रूपरेखा को विश्वसनीयता दी है, क्योंकि यह सरकार एआई तक किसी श्वेत पत्र के माध्यम से नहीं, बल्कि किसी भी लोकतांत्रिक देश द्वारा शुरू किये गये सबसे महत्वाकांक्षी डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना कार्यक्रम के जरिये पहुँची है । यूपीआई ने 2025 में 228 बिलियन से अधिक लेन-देन संसाधित किए, जिनका मूल्य लगभग 3.4 ट्रिलियन डॉलर था, जो दुनिया के वास्तविक समय पर कुल डिजिटल भुगतान का लगभग आधा है और यह वैश्विक स्तर पर वीसा द्वारा संसाधित किये गये कुल लेन-देन से भी अधिक है । जेएएम त्रय ने 2015 से अब तक ?3.48 लाख करोड़ से अधिक की कल्याण बचत प्रदान की है । किसी अन्य देश ने एक ही नीतिगत व्यवस्था के तहत पहचान, भुगतान और पात्रता-अधिकार के वितरण का निर्माण इस स्तर पर नहीं किया है और यही वह आधारशिला है, जिस पर भारत का एआई खड़ा है ।

यदि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का लक्ष्य हर नागरिक को देश से जोड ?ा था, तो एआई अवसंरचना का लक्ष्य हर नागरिक को क्षमता से जोड ?ा है और यहाँ आंकड़े एक चौंकाने वाला अंतर दिखाते हैं: भारत दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत डेटा का उत्पादन करता है, लेकिन यहाँ वैश्विक डेटा-केंद्र क्षमता का केवल लगभग 3 प्रतिशत मौजूद है । अब इस अंतर को उसी इरादे के साथ पाटा जा रहा है, जिसने यूपीआई का निर्माण किया था: तेज, बड़े पैमाने पर और संप्रभु डिजाइन के साथ ।

विचार करें कि भारत मंडपम में एक ही सप्ताह में क्या घोषणाएँ की गईं । माइक्रोसॉफ्ट: 2030 तक वैश्विक दक्षिण के लिए 50 बिलियन डॉलर, जिसमें से पहले ही 17.5 बिलियन डॉलर की भारत के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गयी है । गूगल: अमेरिका-भारत संपर्क पहल, जो पांच वर्षों में 15 बिलियन डॉलर से संचालित होगी । अमेज ? वेब सर्विसेज: महाराष्ट्र में 8.3 बिलियन डॉलर । अदानी समूह: 2035 तक नवीकरणीय ऊर्जा-संचालित एआई डेटा केन्द्रों के लिए 100 बिलियन डॉलर । योटा डेटा सर्विसेज: एनवीडिया के ब्लैकवेल अल्ट्रा चिप्स का उपयोग करके एशिया के सबसे बड़े एआई कंप्यूटिंग हब में से एक के लिए 2 बिलियन डॉलर से अधिक । लार्सन एंड टुब्रो: एनवीडिया के साथ भारत की सबसे बड़ी गीगावाट-स्केल एआई फैक्ट्री बनाने के लिए प्रस्तावित परियोजना । इंडियाएआई मिशन का राष्ट्रीय कंप्यूट क्लस्टर 38,000 जीपीयू पार कर चुका है और इसे 58,000 तक बढ़ाया जा रहा है, जो स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक लागत के लगभग एक तिहाई पर उपलब्ध है । अगले दो वर्षों में एआई अवसंरचना में 200 अरब डॉलर के निवेश का सरकार का लक्ष्य महज आकांक्षा नहीं है; घोषित प्रतिबद्धताएँ इसे हासिल करने के दायरे में लाती हैं ।

केंद्रीय बजट 2026-27 का उद्देश्य इस निवेश को दीघर्कालिक संरचनात्मक लाभ में बदलने का है, जो उन विदेशी कंपनियों के लिए टैक्स होलीडे का 2047 तक विस्तार करता है, जो वैश्विक क्लाउड सेवाओं के लिए भारतीय डेटा सेंटर का उपयोग करती हैं तथा एआई और उच्चतम निर्माण स्टार्टअप्स के लिए 1.1 अरब डॉलर के वेंचर कैपिटल फंड का वचन देती हैं । राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन, जिसका परिव्यय 34,000 करोड़ रुपये से अधिक का है, लिथियम, कॉबाल्ट और दुर्लभ पृथ्वी धातुओं को सुरक्षित करता है, जिन पर एआई और सेमीकंडक्टर का निर्माण निर्भर होता है ।

हालाँकि यह सब तब तक मायने नहीं रखता, जब तक यह लोगों तक नहीं पहुँचता । शिखर सम्मेलन के पहले दिन, 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने नवाचार के लिए जिम्मेदार एआई का उपयोग करने की शपथ ली, यह संख्या गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की मान्यता के लिए प्रस्तुत की गई है । तीस डेटा और एआई लैब्स स्तर 2 और स्तर 3 के शहरों में काम कर रहे हैं, जो 570-लैब नेटवर्क की योजना का पहला प्रयास है, जबकि एआईकोश 7,500 से अधिक डेटासेट और 273 मॉडलों को साझा सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में पेश करता है । जब यह सरकार सत्ता में आई थी, तब भारत में 16 आईआईटी थे; आज 23 हैं । ओपनएआई के सीईओ ने बताया कि भारत चैटजीपीटी का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, जिसके 100 मिलियन साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ता हैं । खपत यहाँ है, और उत्पादन क्षमता रफ्तार पकड़ बना रही है: शिखर सम्मेलन में तीन संप्रभु एआई मॉडल पेश किए गए, जिनमें सर्वम एआई का 105-बिलियन-पैरामीटर व्यापक भाषा मॉडल शामिल है, जिसे पूरी तरह भारतीय कंप्यूटिंग और भारतजेन का परम2 पर प्रशिक्षित किया गया है, एक 17-बिलियन-पैरामीटर बहुभाषी मॉडल, जो सभी 22 अनुसूचित भाषाओं का समर्थन करता है । ये विदेशी मॉडलों के अनुकूल किये गये संस्करण नहीं हैं; इन्हें संप्रभु अवसंरचना पर शुरुआत से बनाया गया है ।

यह भी जानकारी देने योग्य है कि साझेदारी की संरचना अब कैसे तैयार की जा रही है, क्योंकि अब यह विदेशी तकनीक के लाइसेंस के बारे में नहीं है, बल्कि संप्रभु क्षमता के सह-निर्माण के बारे में है । टाटा समूह की ओपनएआई के साथ रणनीतिक साझेदारी स्टारगेट पहल के तहत 100 मेगावाट एआई-तैयार डेटा सेंटर क्षमता के साथ शुरू होगी और इसका विस्तार एक गीगावाट तक किया जाएगा । इससे यह संकेत मिलता है कि भारतीय उद्योग, वैश्विक ज्ञान परिदृश्य में मांग पक्ष से आपूर्ति पक्ष की ओर आगे बढ़ रहा है । शिखर सम्मेलन के दौरान भारत द्वारा पैक्स सिलीका घोषणा पर औपचारिक हस्ताक्षर अमेरिकी-नेतृत्व वाले गठबंधन में देश को एआई, सेमीकंडक्टर और महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षित रखने वाले देशों में शामिल करता है, जिसमें जापान, दक्षिण कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया अन्य सदस्य हैं । इसके साथ ही द्विपक्षीय भारत-अमेरिका एआई अवसर साझेदारी पर हस्ताक्षर किये गये हैं, जो दोनों देशों को महत्वपूर्ण तकनीकों पर नवाचार-प्रवृत्त दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रतिबद्ध करती है, जबकि भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष, 2026 एक और आयाम जोड़ता है, जो संयुक्त कौशल विकास और मापनीय परिणामों से संबंधित है ।

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन श्रृंखला की मेजबानी करने वाला पहला वैश्विक दक्षिण देश केवल एक संवाद आयोजित नहीं कर रहा था, बल्कि उसने यह स्पष्ट कर दिया कि वह किन शर्तों पर प्रतिस्पर्धा करना चाहता है: एक दिल्ली घोषणा पत्र, जो एआई शासन के नियमों को फिर से तैयार करता है, डिजिटल अवसंरचना, जो दुनिया में वास्तविक समय पर होने वाले लगभग आधे भुगतानों को संसाधित करती है, सैकड़ों अरबों की निवेश प्रतिबद्धताएं, पूरी तरह से नए सिरे से बनाए गए संप्रभु मॉडल, और एआई युग की आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा संरचना में प्रवेश । पाणिनि का सबक कभी जटिल नहीं था । संरचना ही बुद्धिमत्ता है । भारत अब उस संरचना का निर्माण कर रहा है ।

उज्ज्वला योजना 3.0 से कबीरधाम में 1339 परिवारों को मिली धुआँ-मुक्त रसोई

नई दृष्टिबिंदु / कबीरधाम

स्वच्छ रसोई केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और सम्मानजनक जीवनशैली की पहचान है। पारंपरिक चूल्हों के धुएँ से जूझ रही महिलाओं को राहत देने के लिए संचालित उज्ज्वला योजना 3.0 आज गरीब और ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रही है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएँ से मुक्ति, बेहतर स्वास्थ्य और सुरक्षित रसोई का लाभ मिल रहा है। कबीरधाम जिला में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत 1339 नए गैस कनेक्शन पात्र हितग्राहियों को प्रदान किए गए हैं। इन कनेक्शनों से उन परिवारों को सबसे अधिक राहत मिली है, जो अब तक लकड़ी, उपले या कोयले से खाना बनाने को मजबूर थे। गैस कनेक्शन मिलने से महिलाओं को धुएँ से मुक्ति मिली है और रसोई का काम भी पहले से आसान व सुरक्षित हो गया है। यह योजना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीब

परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से संचालित की जा रही है। योजना के माध्यम से न केवल स्वास्थ्य की रक्षा हो रही है, बल्कि महिलाओं का समय भी बच रहा है, जिसे वे अब बच्चों की पढ़ाई, स्वरोजगार या अन्य उपयोगी कार्यों में लगा पा रही हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उज्ज्वला योजना ने सामाजिक बदलाव भी लाया है। पहले जहां महिलाओं को ईंधन के लिए जंगलों में घंटों भटकना पड़ता था, वहीं अब घर बैठे सुरक्षित और स्वच्छ ईंधन उपलब्ध है। इससे महिलाओं की सुरक्षा भी बढ़ी है और जीवन स्तर में सुधार आया है। उज्ज्वला योजना 3.0 के तहत दिए गए ये नए कनेक्शन केवल गैस सिलेंडर नहीं, बल्कि बेहतर स्वास्थ्य, सम्मान और सुविधाजनक जीवन की ओर बढ़ाया गया एक महत्वपूर्ण कदम हैं। यह योजना वास्तव में महिलाओं के सशक्तिकरण और स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

उज्ज्वला योजना पात्रता के नए मापदंड उज्जवला योजना 3.0 के संबंध में ऐसे सभी व्यक्ति पात्रता होंगे जो 10 हजार रूपये प्रति माह से कम आय अर्जित करते हो, व्यावसायिक कर का भुगतान ना करते हो, आयकर का भुगतान ना करते हो, परिवार का कोई सदस्य शासकीय सेवा में ना हो, पंजीकृत गैर कृषि उद्यम वाला परिवार ना हो, 50,000 रूपये से अधिक की क्रेडिट सीमा वाला किसान क्रेडिट कार्ड धारित ना हो, एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि का स्वामी ना हो, दो या अधिक फसल मौसमों के लिए 5 एकड़ या इससे अधिक सिंचित भूमिस्वामी धारक ना हो, कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ कम से कम 7.5 एकड़ या इससे अधिक भूमि का स्वामी ना हो, 30 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया (चटाई क्षेत्रफल) वाले घर का स्वामी ना हो (किसी भी सरकारी योजना से प्राप्त घर को छोड़कर), मोटर चालित 3/4 पहिया वाहन, मछली पकड़ने वाली नाव का स्वामी ना हो, यंत्रीकृत 3/4 पहिया कृषि उपकरण का स्वामी ना हो, पूर्व से एल.पी.जी. कनेक्शनधारी ना हो।

खास खबर

व्यवसायी के तौर पर पहचान बना रहीं हैं रेणुबाला

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

सामाजिक परिवेश में केवल गृहिणी की भूमिका तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से सफल व्यवसायी के रूप में पहचान स्थापित कर रही हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के माध्यम से महिलाओं को न केवल सामूहिक मंच मिला है, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह भी मिली है। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के विकासखंड सोनहत अंतर्गत ग्राम पंचायत कटगोड़ी की श्रीमती रेणुबाला जायसवाल आज इसी बदलाव की मिसाल बन चुकी हैं।

रेणुबाला ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ीं और बाद में सत्यम महिला स्व-सहायता समूह में अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से उन्होंने समूह के माध्यम से बैंक से 3 लाख रुपये का ऋण प्राप्त किया और कपड़ा दुकान का व्यवसाय प्रारंभ किया। इस पहल से उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वे आत्मनिर्भर बनीं।

रेणुबाला ने बताया कि शुरुआत में वे समूह की सदस्य के रूप में छोटे लेनदेन से जुड़ी रहीं। बाद में समूह को आरएफ राशि तथा सीआईएफ के रूप में 60 हजार रुपये प्राप्त हुए। सफल संचालन के बाद बैंक से 3 लाख रुपये का ऋण लेकर उन्होंने कपड़ा व्यवसाय को विस्तार दिया। पहले उनके परिवार की वार्षिक आय लगभग 70 हजार रुपये थी, जो अब बढ़कर 2 लाख रुपये से अधिक हो चुकी है। आर्थिक रूप से सशक्त होने के बाद उनके सामाजिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आया है। पहले वे केवल गृहिणी के रूप में जिम्मेदारी निभाती थीं, लेकिन अब परिवार के हर महत्वपूर्ण निर्णय में उनकी सक्रिय भागीदारी होती है। वे परिवार के सदस्यों के साथ आसपास के हाट-बाजारों में भी कपड़े का व्यवसाय कर रही हैं। रेणुबाला अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही है।

होली से पहले 100 से अधिक गुंडे और बदमाशों की ली गई परेड

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने अपराध छोड़ने की दी अंतिम चेतावनी

नई दृष्टिबिंदु / रायगढ़

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने जिले में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और आदतन अपराधियों को अपराध की दुनिया से दूर कर मुख्यधारा में जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए आज शहर के 100 से अधिक निगरानी बदमाशों, गुंडा तत्वों, सजायाफ्ता एवं संदिग्ध प्रवृत्ति के व्यक्तियों को पुलिस कार्यालय में तलब कर उन्हें अपराध छोड़कर सामान्य जीवन जीने की सख्त समझाइश दी। एसएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी चिन्हित बदमाश अपराध से तौबा कर लें और समाज की मुख्यधारा से जुड़कर सम्मानजनक जीवन व्यतीत करें, अन्यथा किसी भी प्रकार की शिकायत या आपराधिक गतिविधि सामने आने पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

होली के मद्देनजर एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि थानों के अभिलेखों में दर्ज निगरानी बदमाशों, गुंडा सूची में शामिल व्यक्तियों, सजायाफ्ता और संदिग्ध अपराधियों को थाने में बुलाकर उन्हें स्पष्ट चेतावनी दी जाए कि वे अपराधों से दूरी बनाकर सकारात्मक कार्यों में संलग्न हों। निर्देशों के पालन में थाना प्रभारियों ने पहले थाने में बदमाशों की क्लास ली। इसी क्रम में आज इन चिन्हित बदमाशों को एसपी कार्यालय में उपस्थित कर एसएसपी शशि मोहन सिंह ने उन्हें अपराध से दूर रहने, नशे और बुरी संगत का त्याग करने तथा अपने जीवन की नई शुरुआत करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि पुलिस ऐसे व्यक्तियों को सुधार का अवसर दे रही है और इस अवसर का लाभ उठाकर वे अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुनः अपराध में लिप्त पाया गया तो रायगढ़ पुलिस द्वारा कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

एसएसपी ने यह भी आश्वस्त किया कि जो व्यक्ति नशा छोड़ना चाहते हैं, उन्हें समाज कल्याण विभाग और पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं रोजगार की समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने हेतु जिला प्रशासन से समन्वय कर सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। इस दौरान कुछ ऐसे व्यक्तियों ने भी जानकारी दी कि उनके विरुद्ध लंबे समय से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जिस पर एसएसपी ने थाना प्रभारियों को उनके अभिलेखों का सत्यापन कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

होली पर्व को ध्यान में रखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने सभी निगरानी एवं आदतन बदमाशों को विशेष रूप से चेतावनी दी कि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, गुंडागर्दी, छेड़खानी या अन्य आपराधिक कृत्यों में संलिप्त न हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि रायगढ़ पुलिस जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करेगा, उसके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई कर न्यायालय के माध्यम से दंड दिलाया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने बदमाशों को उनके पूर्व में किये गये अपराधों का पश्चाताप करने और अपराध छोड़कर पुलिस के मददगार बनाने को कहा, एसएसपी के इस बात पर सभी ने भारत माता की जय के नारे लगाये। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी, डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह, नगर निरीक्षक सुखनंदन पटेल, निरीक्षक प्रशांत राव, उप निरीक्षक गेंदलाल साहू सहित थाना कोतवाली, कोतरारोड, जूटमिल, पूंजीपथरा, खरसिया एवं पुसौर के थाना प्रभारी एवं पुलिस स्टाफ उपस्थित रहे।

पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से विकास को बिजली बिल से मिली राहत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना उपभोक्ताओं के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है। साथ ही भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिले में इस योजना के प्रति आमजन में तेजी से रूचि बढ़ रही है और लोग सोलर पैनल लगाकर बिजली बचत के साथ-साथ ऊर्जा-दाता भी बन रहे हैं।

सूरजपुर जिला के विकासखण्ड राजपुर के ग्राम लड्डवा निवासी विकास शर्मा ने अपने घर के छत पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। सोलर पैनल लगवाने में केंद्र सरकार द्वारा 78 हजार रुपये और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि पहले हर माह उनका बिजली बिल अधिक आता था, परन्तु सोलर पैनल लगने से अब उन्हें अधिक बिजली बिल की चिन्ता से मुक्ति मिलेगी। साथ ही इसके अलावा अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होने पर वह ग्रिड में भी जमा होगी, जिसका उपयोग जरूरत पडने पर भविष्य में किया जा सकता है।

विकास शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बहुत की उपयोगी एवं लाभकारी है। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लेकर बिजली उपभोक्ता से ऊर्जा-दाता बनने की दिशा में कदम बढ़ाएं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपना योगदान दें। श्री शर्मा ने योजना के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

योजना का लाभ लेने कैसे करें आवेदन

प्रधानमंत्री सूर्यघर- मुफ्त बिजली योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को वेबसाईट पीएमसूर्यघर डॉट जीओव्ही डॉट ईन या पीएम सूर्यघर मोबाइल एप पर पंजीयन कर लॉग इन आईडी प्राप्त करना होगा। इसके बाद वेब पोर्टल पर उपलब्ध वेंडर का चुनाव कर बिजली कर्मचारी की मदद से वेब पोर्टल पर पूर्ण आवेदन करना होगा। निर्धारित अनुबंध हस्ताक्षरित होने के पश्चात वेंडर द्वारा छत पर प्लांट की स्थापना एवं डिस्कॉम द्वारा नेट मीटर स्थापित किया जाता है। स्थापित प्लांट के सत्यापन पश्चात शासन द्वारा सब्सिडी ऑनलाईन जारी कर दी जाती है। इस दौरान यदि उपभोक्ता इच्छुक हो तो शेष राशि का प्रकरण ? प्रतिशत ब्याज दर पर बैंक ऋण हेतु बैंकों को जनसमर्थन पोर्टल द्वारा ऑनलाईन प्रेषित किया जाता है, जिससे बैंक के माध्यम से आसानी से लोन मिल जाता है।

बाल विवाह उन्मूलन व बेसहारा बच्चों के संरक्षण पर जोर

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कलेक्टर गोपाल वर्मा की अध्यक्षता में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति तथा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (यथा संशोधित 2021) के तहत गठित विभिन्न समितियों की त्रैमासिक बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले को बाल विवाह मुक्त बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों तथा सड़कों पर रहने वाले, बेसहारा एवं श्रम में संलग्न बच्चों के संरक्षण व पुनर्वास को लेकर से चर्चा की गई।

बैठक में जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा वर्ष 2028-29 तक छत्तीसगढ़ को बाल विवाह मुक्त राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत वर्ष 2025-26 तक कबीरधाम जिले के कुल 40 प्रतिशत ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया जाना है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिक्षा, पंचायत, नगरीय प्रशासन सहित अन्य विभागों के साथ समन्वय कर व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। स्कूलों, ग्राम पंचायतों, धार्मिक स्थलों एवं सामाजिक संगठनों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं।

बैठक में सड़कों पर रहने वाले बच्चों तथा अपशिष्ट संग्रहक, भिक्षावृत्ति एवं बाल श्रम में संलग्न बच्चों का संरक्षण, सुरक्षा एवं पुनर्वास पर भी विस्तृत चर्चा की गई। जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा ऐसे बच्चों की पहचान कर उन्हें आवश्यक देखरेख एवं संरक्षण उपलब्ध कराने हेतु सतत प्रचार-प्रसार और अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इसमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो दिन में सड़कों पर रहते हैं और रात में झुग्गी-झोपड़ी बस्तियों में अपने परिवार के पास लौटते हैं, साथ ही वे बच्चे जो परिवार सहित सड़कों पर जीवन यापन कर रहे हैं।

कलेक्टर ने कहा कि बेसहारा एवं देखरेख की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित अभियान को जिले में और अधिक व्यापक रूप से संचालित किया जाए। उन्होंने संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए ऐसे बच्चों को संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पुनर्वास की मुख्यधारा से जोड़ने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि बाल विवाह उन्मूलन और बच्चों के संरक्षण के बिना समग्र सामाजिक विकास संभव नहीं है, इसलिए इन दोनों विषयों पर सतत और प्रभावी कार्रवाई आवश्यक है।

चमन लाल का घर हो रहा है रोशन पीएम सूर्य घर योजना से

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग अंतर्गत जिला कोंडागांव के ग्राम पंचायत बड़े कनेरा निवासी चमन लाल पवार का परिवार आज शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेकर आत्मनिर्भर और सम्मानजनक जीवन जी रहा है। कभी कच्चे मकान में रहने वाला उनका परिवार अब पक्के, सुरक्षित एवं सौर ऊर्जा से रोशन घर में निवास कर रहा है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मंशानुसार शासकीय योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन का परिणाम है। जिला प्रशासन के सतत मॉनिटरिंग एवं जागरूकता के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ समयबद्ध रूप से पहुँचाया जा रहा है।

आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण श्री पवार वर्षों तक कच्चे मकान में रहने को मजबूर थे। बरसात में छत से पानी टपकना और दीवारों का कमजोर होना आम समस्या थी। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत आवास

की स्वीकृति प्राप्त होने के साथ उन्हें आवास निर्माण में मनरेगा के अंतर्गत 95 मानव दिवस का भी लाभ प्राप्त हुआ, जिससे निर्माण कार्य में आर्थिक संबल मिला और मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित हुआ। आज उनका घर सुरक्षित, स्वच्छ और सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त है।

चमन लाल पवार को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की जानकारी उस समय प्राप्त हुई जब ग्राम पंचायत में आए बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा ग्रामीणों को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की जानकारी दी गई। कर्मचारियों ने सोलर रूफटॉप योजना, शासकीय अनुदान एवं आवेदन प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। जानकारी मिलने के बाद श्री पवार ने योजना के तहत आवेदन किया और अपने नव-निर्मित आवास की छत पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कराया। इस हेतु उन्हें 1 लाख 8 हजार रुपये का शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ। सोलर प्लांट स्थापित होने से अब उनके घर में नियमित एवं पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। घर में रूफटॉप सोलर लगने के बाद बिजली बिल में उल्लेखनीय कमी आई है, जिससे मासिक बचत बढ़ी है। इस बचत का अब वे बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य पारिवारिक आवश्यकताओं में उपयोग कर रहे हैं।

चमन लाल के परिवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन प्राप्त हुआ, जिससे अब उनका परिवार धुएँ से मुक्त रसोई में खाना बना रहा है। वहीं, नल-जल योजना के तहत घर में नल कनेक्शन मिलने से स्वच्छ पेयजल की सुविधा सुनिश्चित हुई है। इससे परिवार की दिनचर्या सरल हुई है और स्वास्थ्य सुरक्षा भी मजबूत हुई है।' प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, मनरेगा, उज्ज्वला योजना, नल-जल योजना एवं पीएम सूर्य घर योजना का समन्वित लाभ चमन लाल पवार के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेकर आया है। उनका घर अब पक्का, स्वच्छ, सुरक्षित और सौर ऊर्जा से रोशन हो रहा है।

जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता: सांसद चिंतामणि

नई दृष्टिबिंदु / सूरजपुर

जल संचय जन भागीदारी अभियान को लेकर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ऑडिटोरियम तिलसिवां सूरजपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप मे सरगुजा सांसद श्री चिंतामणि महराज ने अपनी उपस्थिति दर्ज की। जहां उन्होने वैज्ञानिक खेती और जल संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद चिंतामणि महाराज ने कहा कि पहले लोग नदी, नालों, तालाब, कुओं जैसे जल स्रोतों का पानी का उपयोग पीने एवं दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे, परंतु अधिकांश जलस्रोतों के सूखने या कम होने से भूजल का उपयोग होने लगा। इससे बोरिंग का प्रचलन बढ़ गया किंतु अधिकाधिक उपयोग से अब भूजल स्तर निरंतर गिर रहा है। ऐसे में जल संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

उन्होंने कहा कि हम सभी को न केवल जल का बेहतर एवं सीमित उपयोग करना होगा बल्कि निरंतर उसका संरक्षण भी करना होगा। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, मृदा परीक्षण तथा सिंचाई प्रबंधन से जुड़ी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। सभी सरपंचों को योजनाओं की जानकारी होना आवश्यक है ताकि वे ग्रामवासियों तक इनका लाभ पहुंचा सकें।

उन्होंने आधुनिक एवं वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाने पर बल देते हुए कहा कि जल उपलब्धता के अनुसार फसल चयन करना चाहिए। वैज्ञानिक विधियों से खेती कर हम आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य दे सकते हैं। अच्छी शिक्षा और वैज्ञानिक सोच से ही कृषि

क्षेत्र में समृद्धि लाई जा सकती है। इस कार्यक्रम में विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन की भी जानकारी दी गई।

कार्यक्रम में केंद्रीय भू-जल बोर्ड रायपुर से भू-गर्भ वैज्ञानिक बी अभिषेक व साईं प्रसन्ना पहुंचे थे। जिन्होने जिले से उपस्थित सरपंच, उपसरपंच व अन्य जनप्रतिनिधियों के समक्ष जल संचय को लेकर जागरूकता का प्रचार प्रसार किया। उन्होने डेटा आधारित जलभृत प्रबंधन योजना अंतर्गत जल प्रबंधन से लाभकारी खेती विषय पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनियमित वर्षा, गिरता भूजल स्तर और बढ़ती सिंचाई मांग के कारण पारंपरिक जल प्रबंधन पद्धतियां अब पर्याप्त नहीं रह गई हैं। ऐसे में डाटा ड्रिवन वाटर प्लानिंग सतत कृषि के लिए प्रभावी समाधान है। उन्होंने चेक डैम, परकोलेशन टैंक, फार्म पॉन्ड, माइक्रो इरिगेशन (ड्रिप एवं स्प्रिंकलर), फसल विविधीकरण तथा रिचार्ज संरचनाओं के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही वैज्ञानिकों द्वारा भूमिगत जल दोहन के संबंध मे जानकारी देते हुए बताया कि भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। उन्होने उपस्थितजनों को वर्षा जल संचय के तरीको के संबंध मे विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई और जिले से आए हुए जनप्रतिनिधियों के सवाल व समस्याओं का वैज्ञानिक पद्धति से निदान बताया गया। इसके साथ ही उन्होने जल वृत प्रबंधन एवं वाटर बजटिंग को लेकर विस्तृत चर्चा की।

कलेक्टर एस जयवर्धन ने कहा कि समाज के निचले स्तर तक जल संरक्षण एवं जल संचयन के उपायों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है। उन्होंने जल खपत कम करने और संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सभी को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों में संचालित योजनाओं की प्रभावी मॉनिटरिंग आवश्यक है। सरपंचों के सहयोग से आंगनबाड़ी, स्कूल, स्वास्थ्य विभाग आदि की सेवाओं और बेहतर किया जा सकता है। बेहतर सेवा वितरण के लिए आपसी समन्वय बेहद जरूरी है।

इसके अलावा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने कानून व्यवस्था, साइबर अपराध एवं सड़क सुरक्षा पर भी महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग लालच या झांसे में आकर अपनी गोपनीय जानकारी साझा कर देते हैं। जिससे उनके बैंक खातों से राशि निकाली जा रही है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे ग्रामीणों को इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए जागरूक करें। उन्होंने नशामुक्ति अभियान, अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई में सहयोग तथा हेलमेट पहनने के महत्व पर भी जोर दिया। किसी भी अपराध की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 9575770004 पर देने की अपील की गई, जहां शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाता है।

कार्यक्रम के अंत में वीबी राम जी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ बनाने के लिए सभी उपस्थितजनों को शपथ दिलाई गई। इसके अलावा कार्यक्रम में सभी उपस्थितजनों को कृषि, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, स्वास्थ्य, वन, विद्युत, महिला एवं बाल विकास, उद्यान, आदिवासी विकास तथा मनरेगा के अधिकारियों द्वारा योजनाओं की जानकारी विस्तार से दी गई। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्रीमती रेखा राजवाड़े, जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती स्वाति संत सिंह, जिला पंचायत सदस्यगण, जिला अध्यक्ष सरपंचगण अध्यक्ष, सरपंचगण, उपसरपंचगण, शशिकांत गर्ग, संदीप अग्रवाल, अजय अग्रवाल, जनप्रतिनिधिगण, जिला पंचायत सीईओ विजेंद्र सिंह पाटले, जिला स्तरीय अधिकारी इत्यादि उपस्थित थे।

विद्यार्थी परीक्षा के समय स्वस्थ रहने के लिए करें यह उपाय

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

स्वास्थ्य विभाग द्वारा परीक्षा के समय स्वस्थ रहने के लिए उपाय जारी किया गया है। परीक्षा के समय स्वस्थ रहने के लिए पौष्टिक भोजन को आहार में शामिल करने की सलाह दी गई है। हर रात 7-9 घंटे की नींद लें और तनाव मुक्त रहने के लिए छोटे ब्रेक लेकर हल्की कसरत करें। हाइड्रेटेड रहने के लिए भरपूर पानी पिएं और जंक फूड से बचें, क्योंकि यह सुस्ती और एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है। मस्तिष्क को तेज रखने के लिए बादाम, अखरोट, फल और पत्तेदार सब्जियां खाएं।

पौष्टिक आहार और हाइड्रेशन - भारी भोजन के बजाय दिन में 3-4 बार हल्का और पौष्टिक नाश्ता एवं भोजन करें (जैसे पोहा, उपमा, उबले चने)। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाएं, जो ऊर्जा का स्तर बनाए रखते हैं। खूब पानी, नारियल पानी, या नींबू पानी पिएं, जो ध्यान केंद्रित करने के लिए जरूरी है। बाहर का खाना और बहुत अधिक कैफीन (चाय एवं कॉफी) से बचें। 7-9 घंटे की नींद को प्राथमिकता दें, क्योंकि यह याददाश्त तेज करने के लिए महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के दौरान 50-10 नियम अपनाएं - 50 मिनट पढ़ें और 10 मिनट का ब्रेक लें।

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य -30 मिनट का हल्का व्यायाम या टहलना तनाव कम करता है और मस्तिष्क की कार्यक्षमता सुधारता है। तनाव कम करने के लिए गहरी सांस लें या हल्का संगीत सुनें। पढ़ाई के दौरान आंखों को आराम देने के लिए बीच-बीच में ठंडे पानी से आंखें धोएं। पढ़ाई सही पोश्चर में बैठकर करना चाहिए। झुककर या बिस्तर पर लेटकर पढ़ने के बजाय स्टडी टेबल और कुर्सी का उपयोग करें। सही पोश्चर से गर्दन और पीठ के दर्द से बचाव होता है। अपनी आंखों को आराम देने के लिए 20-20-20 नियम अपनाएं (हर 20 मिनट बाद 20 फीट दूर किसी वस्तु को 20 सेकंड तक देखें)। सब कुछ एक ही दिन में याद करने की कोशिश न करें। छोटे-छोटे लक्ष्य बनाएं।

एसएमएस -2 में सुरक्षा संस्कृति को सुदृढ़ करने के लिए सुरक्षा सप्ताह का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप-2 (एस.एम.एस.-2) में 17 से 24 फरवरी 2026 तक सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कमर्चारियों एवं अधिकारियों में सुरक्षा के प्रति जागरूकता, सतकर्ता तथा उत्तरदायित्व की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना तथा कार्यस्थल पर शून्य-दुर्घटना संस्कृति को प्रोत्साहित करना था।

सुरक्षा सप्ताह के समापन समारोह के मुख्य अतिथि कार्यपालक निदेशक (प्रोजेक्ट्स) पी. के. सरकार थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य महाप्रबंधक (एस.एम.एस.-2) एस. के. घोषाल ने की। इस अवसर पर सेफी चेयरमेन एवं ओए-बीएसपी के अध्यक्ष एन के बंछोर, मुख्य महाप्रबंधक (सुरक्षा एवं अग्निशमन सेवाएँ) देवदत्त सतपथी सहित अन्य मुख्य महाप्रबंधकगण, वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

समारोह का शुभारंभ सुमित कुमार द्वारा सभी उपस्थितजनों को सुरक्षा शपथ दिलाकर किया गया। तत्पश्चात उन्होंने सुरक्षा सप्ताह के दौरान आयोजित गतिविधियों एवं उपलब्धियों पर विस्तृत सुरक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें विभाग की सुरक्षा उपलब्धियों, जोखिम न्यूनीकरण उपायों तथा भविष्य की कायर्योजना का उल्लेख किया गया।

सुरक्षा सप्ताह के दौरान विविध सुरक्षा-उन्मुख कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इनमें क्यू-कार्ड्स एवं टूलबॉक्स वार्ता पर आशु भाषण, सेफ्टी पेंटिंग पोस्टर प्रतियोगिता,

सेफ्टी स्लोगन एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता, औद्योगिक कार्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर क्विज तथा अधिकारियों हेतु सुरक्षा मानकों पर विशेष क्विज प्रतियोगिता शामिल रहीं। सभी प्रतियोगिताओं में कर्मचारियों एवं अधिकारियों की उत्साहपूर्ण एवं सक्रिय सहभागिता रही, जो गत वर्ष की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। यह बढ़ती सहभागिता कार्यस्थल पर सुरक्षा के प्रति सकारात्मक सोच एवं प्रतिबद्धता को परिलक्षित करती है।

सप्ताह के दौरान गैस सेफ्टी एवं लाइफस्टाइल डिजीज विषय पर एक विशेष कायर्शाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा औद्योगिक गैसों के सुरक्षित उपयोग, स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों तथा जीवनशैली जनित रोगों की रोकथाम पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई। समापन समारोह में विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया। अपने प्रेरक उद्बोधन में मुख्य अतिथि पीके सरकार ने सुरक्षा को कार्यसंस्कृति का अभिन्न अंग बनाने, मानकों के कड़ाई से पालन तथा शून्य दुर्घटना के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु निरंतर सजग एवं प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया।

महाप्रबंधक (एस.एम.एस.-2) एन. के. डेथे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत करते हुए सुरक्षा को दैनिक कार्यप्रणाली का स्थायी अंग बनाए रखने पर बल दिया। एस.एम.एस. बिरादरी ने संकल्प लिया कि सुरक्षा सप्ताह केवल प्रतीकात्मक कार्यक्रम न होकर, प्रत्येक कार्यदिवस में सुरक्षा मानकों के सख्त अनुपालन की जीवंत प्रतिबद्धता के रूप में निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। कार्यक्रम का संचालन एस.एम.एस.2 के संजीव सिंह द्वारा किया गया।

खास खबर

मुख्यमंत्री से प्रेस क्लब प्रतिनिधिमंडल ने की सौजन्य मुलाकात, रंगोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किया आमंत्रित

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से रायपुर प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने आज सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रेस क्लब अध्यक्ष मोहन तिवारी, महासचिव गौरव शर्मा, उपाध्यक्ष दिलीप साहू सहित पत्रकार सौरभ सिंह परिहार शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रेस क्लब द्वारा आयोजित किए जाने वाले रंगोत्सव कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने हेतु मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को औपचारिक आमंत्रण दिया। साथ ही पत्रकार हित से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए सकारात्मक पहल की अपेक्षा व्यक्त की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना तथा सभी विषयों पर समुचित पहल करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार आर. कृष्णा दास तथा मीडिया प्रतिनिधिगण उपस्थित थे।

दीक्षा और सूरज बने योगासना स्पोर्ट्स के नेशनल कोच योग साधकों की राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धि

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ के खेल जगत के लिए आज एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान (एनएसएनआईएस), पटियाला, पंजाब में आयोजित गरिमामय कार्यक्रम के दौरान प्रदेश की दो उभरती और प्रतिभाशाली योग विभूतियों, दीक्षा साहू (दुर्ग) और सूरज साहू (बिलासपुर) ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 'योगासना स्पोर्ट्स' के नेशनल कोच बनने का गौरव हासिल किया है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि से पूरे प्रदेश के योग प्रेमियों में हर्ष की लहर है।

दीक्षा साहू योग के प्रति समर्पित परिवार से आती हैं। उनके पिता तिजऊ राम साहू (योगाचार्य, महामंत्री-पतंजलि योग समिति जिला दुर्ग एवं स्टेट जज योगासना स्पोर्ट्स) और माता यशोदा देवी साहू (योग शिक्षिका) के निरंतर मार्गदर्शन और संस्कारों ने उनकी सफलता की नींव रखी है। इसी तरह सूरज साहू ने बिलासपुर जिले का गौरव बढ़ाते हुए अपनी कड़ी मेहनत, अटूट निष्ठा और तकनीकी कौशल के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर कोच एवं जज के रूप में अपना स्थान सुनिश्चित किया है। दोनों नवनियुक्त नेशनल कोचों ने अपनी इस सफलता का श्रेय अपने मार्गदशर्कों गोस्वामी जयंत विष्णु भारती (प्रेसिडेंट-छत्तीसगढ़ योगासना स्पोर्ट्स), अनुप बंसल (सह-राज्य प्रभारी-भारत स्वाभिमान न्यास, छत्तीसगढ़) के साथ मास्टर आनंद सिंह (डायरेक्टर - स्वालंबी योग एकेडमी) के विशेष तकनीकी मार्गदर्शन, कठिन प्रशिक्षण को दिया है। पटियाला से नेशनल कोच की उपाधि प्राप्त करने के बाद अब दीक्षा और सूरज की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। अब वे न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण राष्ट्र के उभरते योग खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करेंगे और आगामी राष्ट्रीय योगासना प्रतियोगिताओं में निर्णायक की महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे।

किसान पोर्टल एवं ई-समृद्धि पोर्टल में किसानों का किया जा रहा पंजीयन

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) योजना अंतर्गत प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) में किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल एवं ई-समृद्धि पोर्टल पर किया जा रहा है। योजनांतर्गत खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन तथा रबी विपणन वर्ष 2026-27 हेतु चना, मसूर, सरसों फसल की उपज का पंजीयन जारी है। जिले में प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के 15 उपार्जन केन्द्रों तथा एक एफपीओ स्वर्ण उपज महिला किसान उत्पादक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सुकुलदैहान को अधिसूचित किया गया है। जिनमें घुमका, पदुमतरा, सोमनी, छुरिया, कुमरदा, गैंदाटोला, गहिराभेड़ी, डोंगरगांव, तुमड़ीबोड, कोकपुर, खुर्सीपार, डोंगरगढ़ अछोली, मुसरा, मोहारा एवं लाल बहादुर नगर शामिल हैं।

उप संचालक कृषि टीकम सिंह ठाकुर ने बताया कि शासन द्वारा पारदर्शिता की दृष्टि से गिरदावरी (डिजिटल क्रॉप सर्वे) को एकीकृत पोर्टल से लिंक किया गया है। कृषकों को अपने नजदीकी सेवा सहकारी समिति जो उस क्षेत्र का अधिसूचित उपार्जन केन्द्र है, वहां पहुंचकर ई-समृद्धि पोर्टल अथवा एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना अनिवार्य है। किसानों को उपज को उपार्जन केन्द्र में लाने के पूर्व अच्छे सफाई एवं अवांछित तत्वों को पृथक कर उच्चगुणवत्तायुक्त बीजों को उपार्जन केन्द्र में लाना होगा। उपज को समर्थन मूल्य में विक्रय करते समय शासन द्वारा निर्धारित फेयर एवरेज क्वालिटी गुणवत्ता की जांच करने के बाद फसल की खरीदी की जाएगी। जिसे सुनिश्चित करने के लिए नमी मापक यंत्र और इलेक्ट्रॉनिक कांटे जैसे उपाय किए जाएंगे। किसान अपनी उपज को सेवा सहकारी समितियों में लाने से पूर्व 100 ग्राम दानों या बीजों में दानों में मिट्टी, कंकड़, धूल, भूसा व अन्य अपशिष्ट पदार्थ, अन्य दालों की मिलावट, क्षतिग्रस्त दाने, हल्के क्षतिग्रस्त दाने, अपरिपक्वएवं सिकुड़े हुए दाने, कीटग्रस्त एवं फफूंदीग्रस्त दाने, नमी की मात्रा, मिश्रण मिलावट एवं अशुद्ध मिश्रण, सरसों के छोटे कमजोर बीजों में अधिकतम छूट अलग-अलग फसलवार अधिकतम 2 से 6

प्रतिशत तक किया जा सकता है।

किसान अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों के माध्यम से संबंधित सेवा सहकारी समिति में आवेदन पत्र के साथ ऋण पुस्तिका, बी-1, पी-2, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छायाप्रति जमा कर एकीकृत किसान पोर्टल एवं ई-समृद्धि पोर्टल में पंजीयन करा सकते हैं। योजना अंतर्गत शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिले के लिए चिन्हांकित केंद्रीय एजेंसी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) द्वारा पंजीकृत कृषकों की फसलों का उपार्जन किया जाएगा। जिसके लिए समर्थन मूल्य सोयाबीन 5328 रूपए प्रति क्विंटल, अरहर 8000 रूपए प्रति क्विंटल तथा चना 5875 रूपए प्रति क्विंटल, मसूर 7000 रूपए प्रति क्विंटल एवं सरसों 6200 रूपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

प्राइस सपोर्ट स्कीम (पीएसएस) में किसानों का पंजीयन एकीकृत किसान पोर्टल एवं नाफेड द्वारा संचालित ई-समृद्धि पोर्टल माध्यम से दलहन एवं तिलहन फसलों की ऑनलाईन पंजीयन कर खरीदी की जा रही है। इससे किसानों को समर्थन मूल्य की राशि सीधे उनके बैंक खातों में प्राप्त होगी। यह योजना दलहन-तिलहन क्षेत्र के विस्तार और किसानों की आय वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका सिद्ध होगी।

वार्षिक उत्सव या राजनीतिक मंच?

वार्षिक उत्सव या राजनीतिक मंच? विरोध से पहले कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी से गरमाई सियासत

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

राजनांदगांव जिले के एक प्रमुख महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव को लेकर शुरू हुआ विवाद अब खुलकर राजनीतिक रंग ले चुका है। कार्यक्रम से पहले कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी ने पूरे मामले को और अधिक तूल दे दिया है।

कांग्रेस का आरोप है कि महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव, जो परंपरागत रूप से विद्यार्थियों की प्रतिभा, सांस्कृतिक गतिविधियों और उपलब्धियों का मंच रहा है, उसे एक विशेष राजनीतिक दल के प्रचार का माध्यम बनाया जा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि शैक्षणिक परिसर को दलगत राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस ने स्पष्ट किया है कि यदि शैक्षणिक संस्थानों में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रुका तो वे इस मुद्दे को लेकर व्यापक स्तर पर लोकतांत्रिक आंदोलन करेंगे।

बसंतपुर थाना में जुटे पदाधिकारी

घटना के बाद कांग्रेस पदाधिकारी बड़ी संख्या में बसंतपुर थाना पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए गिरफ्तार नेताओं की तत्काल रिहाई की मांग की। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार, प्रदेश सचिव मेहुल मारू, कांग्रेस नेता अमित चंद्रवंशी, ब्लॉक अध्यक्ष लक्ष्मण साहू, संदीप जायसवाल और वीरेंद्र चंद्राकर ने प्रशासन से निष्पक्षता बरतने की अपील की है।

विरोध की तैयारी, पहले ही हिरासत

कांग्रेस नेताओं के अनुसार वे कथित भाजपाकरण के खिलाफ शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराने की तैयारी में थे। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई नेताओं को उनके घरों से हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के सचिव विशु अजमानी, पूर्व पार्षद ऋषि शास्त्री, एनएसयूआई नेता राजा यादव, युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष ऋषभ निर्मलकर, सागर ताम्रकार, संजय साहू और हनी सहित अन्य कार्यकर्ता शामिल हैं। कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताते हुए कड़ी आपत्ति दर्ज की है। नेताओं का कहना है कि शांतिपूर्ण विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है और पुलिस की यह कार्रवाई असहमति की आवाज को दबाने का प्रयास है।

मुख्यमंत्री ने संघ की 100 वर्षों की गौरवगाथा पर आधारित फिल्म 'शतक' को टैक्स-फ्री करने की घोषणा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने राजधानी रायपुर स्थित जोरा मॉल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गौरवशाली 100 वर्षों की यात्रा पर आधारित फिल्म शतक देखी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय के साथ मंत्रिमंडल के सदस्य तथा जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। मुख्यमंत्री साय ने फिल्म के प्रदर्शन के बाद कहा कि शतक केवल एक फिल्म नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, जनसेवा और समर्पण की सतत साधना का सजीव चित्रण है।

उन्होंने कहा कि संघ की प्रेरक गाथा जन-जन तक पहुँचे और नई पीढ़ी को राष्ट्र सेवा की भावना से प्रेरणा मिले, इस उद्देश्य से छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को टैक्स-फ्री करने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि पूजनीय डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार जी के तप, त्याग और दूरदर्शी विचारों से प्रारंभ हुई इस यात्रा को पूजनीय माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जी ने नई दिशा और संगठनात्मक शक्ति प्रदान की। एक शताब्दी का यह इतिहास लाखों स्वयंसेवकों के अनुशासन, समर्पण और ह्यराष्ट्र प्रथमह्ल की भावना का जीवंत प्रमाण है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने शिक्षा, सेवा और सामाजिक समरसता के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचने का कार्य किया है। आपदा, संकट और सामाजिक आवश्यकताओं के समय संघ कार्यकर्ताओं की सेवा भावना ने समाज को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनसेवा और राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की यही प्रेरणा शासन के कार्यों में भी मार्गदर्शक बनती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि फिल्म शतक युवाओं सहित समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगी।

मंत्री यादव की पहल - दुर्ग को मिलेगा नया फ्लाईओवर, संगीत महाविद्यालय और आधुनिक सर्किट हाउस

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

विधानसभा में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी द्वारा प्रस्तुत छत्तीसगढ़ संकल्प बजट में दुर्ग शहर के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं। यह उपलब्धियाँ दुर्ग शहर विधायक एवं कैबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव के सतत प्रयासों का परिणाम हैं। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। दुर्ग के नागरिकों ने भाजपा पर जो विश्वास जताया है, उसी का परिणाम है कि शहर में विकास कार्यों की रफ्तार अब और तेज होगी।

मंत्री गजेन्द्र यादव लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जनता की समस्याएँ सुनते रहे हैं और उन्हें प्राथमिकता के साथ पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। महाराजा चौक और पोटिया चौक पर नए फ्लाईओवर का निर्माण से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी और आवागमन सुगम होगा। विजय नगर से उरला मार्ग पर अंडरब्रिज निर्माण से रेल फाटक की समस्या से राहत मिलेगी और समय की बचत होगी। दुर्ग से पोटियाकला होते हुए हनोदा तक

फोरलेन सड़क से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का बेहतर संपर्क होगा।

नेशनल हाईवे तक एप्रोच रोड निर्माण से बाहरी क्षेत्रों से आने-जाने में सुविधा बढ़ेगी। शहर में नई स्ट्रीट लाइट व्यवस्था से सुरक्षा और सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। संगीत महाविद्यालय की स्थापना कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा तथा स्थानीय युवाओं को शिक्षा का नया अवसर मिलेगा। नए सर्किट हाउस का निर्माण से शहर में आने वाले अतिथियों और अधिकारियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त व्यवस्था तैयार होगी।

इन सभी विकास कार्यों से दुर्ग शहर के आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध होंगी। आने वाले समय में दुर्ग विकास के नए आयाम स्थापित करेगा और प्रदेश के अग्रणी शहरों में अपनी पहचान और मजबूत करेगा। बजट में शामिल किये गए कार्य है - दुर्ग विधानसभा अंतर्गत 7वीं बटालियन के आंतरिक सड़क निर्माण 6.50 किमी । दुर्ग नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत महत्वपूर्ण सड़क चौड़ीकरण, उन्नयन एवं सौन्दर्यीकरण तथा चौक चौराहो का उन्नयन कार्य 10 किमी। दुर्ग के परेतिन चौक से उरला फाटक तक सड़क निर्माण। दुर्ग विधानसभा क्षेत्र के धमधा बेमेतरा मुख्य मार्ग से करहीडीह पहुंच मार्ग 1.50 किमी।

रायपुर नाका से सिंधी कॉलोनी होते हुए ठगड़ा बांध पहुंच मार्ग निर्माण 3 किमी तथा मोहन ओम परिसर से उरला मेन रोड तक पहुंच मार्ग। दुर्ग कमर्चारी नगर के आंतरिक सड़क का डामरीकरण 1.50 किमी। दुर्ग जयंती नगर से नेशनल हाईवे तक सड़क एवं नाली निर्माण 1.50 किमी तथा बेलौदी एनिकट से प्रेमनगर होते हुए धमधा बेमेतरा मुख्य मार्ग तक पहुंच मार्ग 3 किमी। दुर्ग साइंस कॉलेज से रेलवे स्टेशन केनाल रोड तक चौड़ीकरण, दुर्ग के पुलगाँव नाला का डायवर्सन एवं सुदृढ़ीकरण कार्य। दुर्ग विकासखंड के तिरगा जलाशय का जीर्णोधार एवं लाईनिंग कार्य।

दुर्ग जिले के गनियारी जलाशय का जीर्णोधार एवं लाईनिंग कार्य। दुर्ग विधानसभा अंतर्गत गाँधी चौक से हेमचंद विश्वविद्यालय पोटियाकला तक फोरलेन सड़क, सड़क निर्माण 03 किमी एवं हेमचंद वि.वि.से बोरसी हनोदा मार्ग तक 02 किमी तक। दुर्ग के अंतर्गत नवीन सर्किट हाउस भवन का निर्माण कार्य। दुर्ग में शासकीय संगीत महाविद्यालय निर्माण। साइंस कॉलेज दुर्ग में अतिरिक्त कक्ष निर्माण। दुर्ग विधानसभा अंतर्गत महाराजा चौक से ईरानी डेरा चौक तक 1.80 किमी स्ट्रीट लाइट लगाने का कार्य। दुर्ग विधानसभा के विजय नगर से उरला मार्ग पर अंडरब्रिज निर्माण।

तृप्ति को मिला अमृत कुंभ सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

हिंदी भाषा भारतीय संस्कृति, ज्ञान परम्परा और राष्ट्रीय भावना की वह जीवंत धारा है,जिसने देश को एक सूत्र में बांधे रखा है। मातृभाषा के प्रति सम्मान, अभिव्यक्ति में सहजता तथा ज्ञान विस्तार की दृष्टि से हिंदी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस दिशा में हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा संचालित गतिविधियां प्रशंसनीय हैं।

इसी क्रम में फाउंडेशन द्वारा गत दिनों अमृत कुंभ सम्मान व अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड पुरस्कार वितरण समारोह सी डी देशमुख ऑडिटोरियम नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय वाइडनर इंग्लिश मीडियम स्कूल की शिक्षिका तृप्ति दुबे को उनकी स्वरचित रचना के लिये अमृत कुंभ सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें लद्दाख के उप राज्यपाल द्वारा प्रदान किया गया। तृप्ति की इस उपलब्धि पर विद्यालय परिवार, उनके ईष्ट मित्रों व परिजनों ने बधाई देते हुये शुभकामनायें प्रेषित की हैं।

'सांड की आंख' से लेकर 'पिंक' तक : तापसी पन्नू की इन फिल्मों ने बदला समाज का नजरिया

भारतीय सिनेमा पर लंबे समय से अभिनेताओं और बड़े स्तर की फिल्मों का कब्जा रहा है, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और दर्शक भी खुद को थिएटर में सीटी बजाने से नहीं रोक पाए। अब बदलते समय के साथ महिला प्रधान फिल्मों ने भी हिंदी सिनेमा में अलग जगह बना ली है और लगभग हर अभिनेत्री बिना किसी मेन लीड के सहारे फिल्मों में अपनी धाक जमा रही है। आज तापसी पन्नू की 'अस्सी' सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और अगर उनके करियर के पन्नों को पलटा जाए तो उन्होंने कई ऐसी महिला प्रधान फिल्में की हैं, जिन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। सिर्फ सिनेमाघर ही नहीं, बल्कि ओटीटी पर भी तापसी ने महिला प्रधान फिल्मों से फैंस का दिल जीता है। उनकी साल 2019 में आई 'बदला' ने ओटीटी पर नई लहर की शुरुआत की थी, जिसमें अपने प्रेमी के ही मर्डर केस में फंसी तापसी खुद के बेकसूर साबित करने की लड़ाई लड़ती हैं। 'बदला' में उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी और आईएमडीबी पर रेटिंग 7.7 थी। 'बदला' से पहले तापसी ने 'पिंक' में काम किया था, जिसका डायलॉग 'नो मींस नो' ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म में महिलाओं की मर्जी और उनकी भावनाओं को तवज्जो दी थी और समाज की संकीर्ण धारणाओं पर प्रहार किया था।

साल 2020 में तापसी 'थप्पड़' को लेकर आईं, जिसमें महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा को उजागर किया गया और बताया गया कि शुरुआत एक थप्पड़ से ही होती है। फिल्म में सिर्फ 'एक थप्पड़' के कारण रिश्तों और सम्मान के सवाल को उठाया गया है, जिसके लिए इसे खूब सराहना मिली। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की और वर्ल्ड वाइड 44 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया।

'सांड की आंख' फिल्म को भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिसमें तापसी ने प्रकाशी तोमर का रोल निभाया था। यह फिल्म साठ साल की दो बहनों चंद्रो और प्रकाशी के जीवन पर बनी थी, जो 60 साल की उम्र के बाद निशानेबाजी में आई और कई पुरस्कार भी अपने नाम किए। फिल्म में पितृसत्तात्मक और रुढ़िवादी सोच को भी बखूबी दिखाया गया। साल 2021 में आई रश्मि रॉकेट भले ही पर्दे पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन फिल्म भारतीय महिला खिलाड़ियों के संघर्ष पर बनी है। फिल्म में छोटे से गांव से निकली रश्मि वीरा अपने सपनों को उड़ान देने के लिए कई संघर्षों से गुजरती है। फिल्म में महिला खिलाड़ियों के साथ होने वाले भेदभाव, जेंडर टेस्टिंग और हाइपरएंड्रोजेनिज्म के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है।

मैं कभी बॉलीवुड छोड़ना नहीं चाहती थी लेकिन परिस्थितियों ने मौके तलाशने के लिए 'पुश' किया

एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा दुनियाभर में मशहूर हैं। उन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में काम किया है और अपने करियर में कई शानदार फिल्में की हैं। अपने करियर के पीक समय में उन्होंने बॉलीवुड छोड़ दिया था और हॉलीवुड का रुख किया था। लेकिन अब प्रियंका चोपड़ा ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि वे कभी बॉलीवुड छोड़ना नहीं चाहती थीं, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें हिंदी सिनेमा से बाहर मौके तलाशने के लिए 'पुश' किया।'

मैं कभी बॉलीवुड नहीं छोड़ना चाहती थी

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक के अपने सफर पर बात करते हुए प्रियंका चोपड़ा ने खुलकर अपनी दिल की बात शेयर की। प्रियंका ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि मैं कभी बॉलीवुड छोड़ना चाहती थी। लेकिन जब मैं हिंदी फिल्मों में काम कर रही थी, तो कई वजहों से खुद को थोड़ा सीमित महसूस करती थी। मैं अपने काम का दायरा बढ़ाना चाहती थी। एक कलाकार के तौर पर मैं कुछ नया और रोमांचक करना चाहती थी। इसी सोच ने मुझे दूसरे मौके तलाशने के लिए प्रेरित किया।' उन्होंने आगे कहा, 'इसी तलाश ने मुझे अमेरिका पहुंचाया। अब करीब 12 साल बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस मुकाम पर हूं, जहां मैं अपने मनपसंद और बेहतरीन प्रोजेक्ट्स चुन सकती हूं। लेकिन यह सफर बिल्कुल आसान नहीं था।'

मुझे दोनों इंडस्ट्री में काम करना पसंद है

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे मेरी इंडियन फिल्मों से प्यार है। मैं बहुत खुश हूं कि वापस भारत में आकर वाराणसी फिल्म के लिए काम कर रही हूं। मैं कभी भी इन दोनों में से किसी एक को चुनना नहीं चाहूंगी। मैंने कभी ऐसा किया भी नहीं। मुझे लगता है कि मैं दोनों इंडस्ट्री के बीच संतुलन बनाकर चलती हूं और मुझे दोनों इंडस्ट्री में काम करना पसंद है। दोनों जगह काम करने का तरीका कई मायनों में अलग है, ठीक वैसे ही जैसे उनकी संस्कृतियां अलग होती हैं। लेकिन अब मेरा दिमाग दोनों तरीकों से सोचने का आदी हो चुका है। यह अपने आप में एक अनोखा, शानदार और मजेदार अनुभव है।'

कोंकणा सेन शर्मा की 'अक्यूज्ड' का ट्रेलर रिलीज, प्रतिभा रांटा का दिखा दमदार अंदाज

इस महीने की शुरुआत में नेटफ्लिक्स ने इस साल आने वाले अपने प्रोजेक्ट्स की घोषणा की थी। इसमें एक नाम शामिल था नेटफ्लिक्स की फिल्म 'अक्यूज्ड' का। कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज हो गया है। यह एक सस्पेंस-थ्रिलर ड्रामा है।

'अक्यूज्ड' पोलैंड में सेट सस्पेंस ड्रामा है। कहानी के केंद्र में हैं डॉ. गीतिका (कोंकणा सेन शर्मा), जो एक जाने-माने हॉस्पिटल में सबसे कम उम्र की हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पर काम कर रही हैं। डॉ. गीतिका एक मशहूर एलजीबीटीक्यू गायनेकोलॉजिस्ट हैं। वह डीन बनने की तैयारी कर रही हैं। गीतिका अपनी लेस्बियन पार्टनर मीरा (प्रतिभा रांटा) के साथ मिलकर एक बच्चे को एडॉप्ट करने की प्लानिंग करती हैं। लेकिन तभी सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल किया जाता है। डॉ. गीतिका पर यौन दुराचार के गंभीर आरोप लगते हैं। उन्हें काफी कुछ कहा जाता है। इससे डॉ. गीतिका की जिंदगी और करियर, दोनों में भूचाल आ जाता है। जनता और अधिकारियों का शक बढ़ता है और सच्चाई धुंधली होती जाती है। इसके पीछे कौन है और क्या वजह है, ये फिल्म देखने पर पता चलेगा।

अनुभूति कश्यप ने किया निर्देशन

इस सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म को अनुराग कश्यप की बहन अनुभूति कश्यप ने डायरेक्ट किया है। वो इससे पहले आयुष्मान खुराना की 'डॉक्टर जी' का भी निर्देशन कर चुकी हैं। वहीं करण जौहर के डिजिटल प्रोडक्शन हाउस धर्माटिक एंटरटेनमेंट के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया गया है। फिल्म की कहानी भी अनुभूति कश्यप ने ही लिखी है। फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा और प्रतिभा रांटा के अलावा आदित्य नंदा और सुकांत गोयल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। 'अक्यूज्ड' 27 फरवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।

फरहान अख्तर के साथ अगला प्रोजेक्ट करेंगे विजय वर्मा

जल्द ही विजय वर्मा, फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी के एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ काम एक प्रोजेक्ट करने वाले हैं। विजय वर्मा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर फरहान अख्तर और रितेश सिधवानी से मिले एक कार्ड की तस्वीर शेयर की। एक्टर ने प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा छिपाकर रखा। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर वह काफी एक्साइटेड हैं, इस बात का जिक्र विजय वर्मा ने किया है। विजय वर्मा के पास कई और फिल्में हैं। वह 'मटका किंग' नाम की एक फिल्म कर कर रहे हैं। इसके अलावा वह एक और फिल्म 'फैमिली बिजनेस' कर रहे हैं, इसमें अनिल कपूर भी नजर आएंगे। इसके अलावा वह 'लस्ट स्टोरी 3' में भी दिखाई देंगे।

'कॉकटेल 2' में किस किरदार में नजर आएंगी रश्मिका मंदाना और कृति सेनन?

अपकमिंग फिल्म 'कॉकटेल 2' को लेकर लोगों में उत्सुकता है। रिलीज से पहले इस फिल्म को लेकर काफी चर्चा होने लगी है। साल 2012 में रिलीज हुई फिल्म 'कॉकटेल' को दर्शकों ने खूब प्यार दिया था। अब इसके सीक्वल 'कॉकटेल 2' में रश्मिका मंदाना, कृति सेनन और शाहिद कपूर लीड रोल में हैं। इसमें रश्मिका मंदाना और कृति सेनन के रोल को लेकर एक अपडेट सामने आई है।

क्या होगा कृति और रश्मिका का रोल?

फिल्म 'कॉकटेल 2' की कहानी को लेकर लोगों में दिलचस्पी बढ़ रही है। इस बीच फिल्म में रश्मिका मंदाना और कृति सेनन के रोल को लेकर अपडेट आई है। ओसीडी टाइम्स के मुताबिक फिल्म में कृति सेनन और रश्मिका मंदाना एक लेस्बियन कपल का रोल करेंगी।

कब पूरी हुई फिल्म की शूटिंग?

हालांकि, प्रोडक्शन टीम ने फिल्म की कहानी के बारे में अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। इसलिए दर्शकों को कोई नतीजा निकालने से पहले प्रोडक्शन हाउस की तरफ से दी गई जानकारी का इंतजार करना होगा। डायरेक्टर होमी अदजानिया ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी थी कि फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई है।

दर्शकों को क्यों हैं उम्मीदें?

आपको बता दें कि ओरिजिनल फिल्म 'कॉकटेल' (2012) में दीपिका पादुकोण, डायना पेंटी और सैफ अली खान ने अहम किरदार निभाया था। इस फिल्म ने अपनी अलग कहानी के लिए तारीफें बटोरी थीं। ऐसे में फिल्म के सीक्वल से लोगों को काफी उम्मीदें हैं।

कब रिलीज होगी फिल्म?

फिल्म 'कॉकटेल 2' की रिलीज का अभी एलान नहीं हुआ है। हालांकि मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मेकर्स इसे इस साल सितंबर तक रिलीज कर सकते हैं। यह फैसला इसलिए किया गया है, ताकि शाहिद कपूर की फिल्म 'ओ रोमियो' को कुछ वक्त मिल सके।

अनुभव सिन्हा को नहीं होती बॉक्स ऑफिस नंबर्स की चिंता

अनुभव सिन्हा की 'अस्सी' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। देश में होने वाली दुष्कर्म की घटनाओं पर आधारित यह फिल्म अपनी घोषणा के बाद से ही चर्चाओं में है। हालांकि, जब इस फिल्म की घोषणा हुई थी, तो लोगों को लगा था कि अनुभव सिन्हा अपने गृहनगर वाराणसी के अस्सी घाट की कहानी लेकर आ रहे हैं। लेकिन जल्द ही पता चल गया कि कहानी एक संवेदनशील और जरूरी मुद्दे पर आधारित है। फिल्म को लेकर निर्देशक का कहना है कि कहानी का मूल विचार समाचार पत्रों की सुर्खियों से ही प्रेरित है।

लोगों को अब अपराध की गंभीरता से फर्क नहीं पड़ता

बातचीत में अनुभव सिन्हा ने फिल्म को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि हमारे चारों ओर सूचनाओं की भरमार के कारण, दर्शकों को किसी अपराध की गंभीरता का एहसास कराना कठिन होता जा रहा है। फिर चाहे वह बलात्कार जैसा जघन्य अपराध ही क्यों न हो। अब यह उतना मायने नहीं रखता कि आपकी आंखों के सामने क्या है, बल्कि यह मायने रखता है कि क्या आकर्षक है। आप उससे विचलित हो जाते हैं। इसलिए यह कोई गपशप या सनसनीखेज कहानी हो सकती है, क्योंकि यह अब सनसनीखेज नहीं रह गई है।

बॉक्स ऑफिस नंबर्स गपशप का विषय

बॉक्स ऑफिस नंबर्स और क्रिटिक्स की रेटिंग को लेकर निर्देशक का कहना है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और समीक्षाओं में स्टार रेटिंग जैसी मामूली बातें भी चर्चा को एक संख्या तक सीमित कर देती हैं। जबकि असल मुद्दा चिंता का विषय होना चाहिए। ये आंकड़े गपशप का अच्छा जरिया हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शक इसे समझ रहे होंगे। उन्हें यह समझ नहीं आता कि दुनिया भर में कुल कमाई, भारत में कुल कमाई और भारत में शुद्ध कमाई क्या होती है। उन्हें यह नहीं पता कि निर्माता को बताई गई रकम का 50% से भी कम मिलता है। 400 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये और 800 करोड़ रुपये जैसे आंकड़े तो बहुत ही महत्वाकांक्षी लगते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि दर्शक इन आंकड़ों को गंभीरता से नहीं लेंगे। अगर मैं कर सकता तो मैं अपने आंकड़े घोषित नहीं करता, चाहे वे कितने भी अच्छे या बुरे क्यों न हों। लेकिन मैं इसे नहीं रोक सकता।

कोर्टरूम के अंदर के माहौल से असल में हुआ वाकिफ

कोर्टरूम को लेकर अनुभव ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी दो वरिष्ठ महिला वकील दोस्त हैं। हमने उन्हें कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, 'आप लोग इतनी गंदी कोर्ट शूटिंग करते हो। आपने कभी कोर्ट देखी है?' मैंने कहा, 'जी हां, सुप्रीम कोर्ट।' तो उन्होंने कहा, 'इसीलिए! आपने वो शांत, परिष्कृत कोर्टरूम देखा है जहां हर कोई चुपचाप सुनता रहता है। लेकिन फिल्म का मामला उस कोर्ट में नहीं जाएगा। अगले ही दिन मैंने नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट का दौरा किया और वहां का नजारा देखकर दंग रह गया। मुझे एहसास हुआ कि मैंने फिल्म 'मुल्क' के कोर्टरूम सीन गलत तरीके से फिल्माए थे। यह कोर्टरूम बहुत भीड़भाड़ वाला और अव्यवस्थित है। मुझे कोर्टरूम की यह शीतलता बहुत पसंद आई। कोर्टरूम अपने काम में इतना मशगूल रहता है जबकि आपका जीवन इस पर निर्भर करता है।

छोटे शहरों में भी देखी जाती हैं 'अस्सी' जैसी फिल्में

अनुभव सिन्हा का मानना है कि वो इस धारणा को तोड़ देंगे कि 'अस्सी' जैसी फिल्में जनता के लिए नहीं होती हैं। उन्होंने अपने जमीनी स्तर के अभियान 'चल सिनेमा चलें' के तहत भारत के 40 दूसरे दर्जे के शहरों का दौरा किया है। उनका कहना है कि यह एक गलत धारणा है। उन्होंने कहा कि अब मैं कह सकता हूं कि दूसरे दर्जे के शहरों में इस तरह की फिल्में नहीं देखी जातीं। वे सिर्फ जवान या कांतारा जैसी फिल्में देखते हैं। बेशक उन्हें वो फिल्में ज्यादा पसंद आती हैं। लेकिन इन फिल्मों में भी उनकी काफी दिलचस्पी है। दिक्कत ये थी कि हम उन्हें सही तरीके से फिल्म नहीं दिखा पा रहे थे। इसलिए इस बार मेरा पूरा अभियान घर-घर जाकर प्रचार करने पर केंद्रित है पिछले दो महीनों से हम छोटे शहरों में फिल्म का प्रचार कर रहे हैं।

क्षेत्र की जनता को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना मेरी नैतिक जिम्मेदारी-विधायक ललित चंद्राकर

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में सड़क निर्माण और विकास कार्यों के लिए बजट में 3150 .00 लाख का प्रावधान

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर के अथक प्रयासों से छत्तीसगढ़ बजट 2026-27 में दुर्ग जिले के लिए 3150.00 लाख की लागत से विभिन्न सड़क निर्माण और विकास कार्यों का प्रावधान किया गया है। ये कार्य क्षेत्र के विकास और आवागमन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

विधायक ललित चंद्राकर ने कहा, "यह बजट दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हमने क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया है और आगे भी करते रहेंगे। इन सड़क निर्माण कार्यों से क्षेत्र के निवासियों को आवागमन में सुविधा होगी और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने आगे कहा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश निरंतर विकास की ओर अग्रसर है। मैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव का और वित्त मंत्री ओपी चौधरी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आपके मार्ग दर्शन से हमारा प्रदेश व क्षेत्र विकास की ओर अग्रसर है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों में शामिल कार्य

बांधा तालाब नगपुरा साहेब पारा से अंजनिया अंजोरा पहुंच मार्गः लंबाई 3.00 कि.मी. का निर्माण कार्य, भोथली से तिरगा पहुंच मार्ग लंबाई 2.00 कि.मी. का जीणोद्धार एवं मजबूतीकरण कार्य, और पंचायत निकुम से सड़क निर्माण व चौड़ीकरण मार्ग अटल चौक से गोडेला मोड़ तक लंबाई 3.00 कि.मी. के लिए 280.00 लाख का प्रावधान। नगपुरा से अंजोरा डाबा मार्ग निर्माण कार्य पुल पुलिया सहितः लंबाई 2.90 कि.मी. के लिए 270.00 लाख का प्रावधान है।

मुख्य मार्ग से बाल संप्रेषण गृह, एन.सी.सी. 37 बटालियन एवं हाईस्कूल पुलगांव, पहुंच मार्ग पुल पुलिया सहितः लंबाई 2.00 कि.मी. के लिए प्रावधान। जैन मंदिर के बाजू से बोरई गनियारी मार्ग से बाबा देवता तक पहुंच मार्ग पुल पुलिया सहित निर्माण कार्यः लंबाई 1.50 कि.मी. के लिए 140.00 लाख का प्रावधान। दुर्ग शहर के कोटनी नगपुरा पहुंच मार्ग का चौड़ीकरण कार्य पुल पुलिया सहितः लंबाई 10.00 कि.मी. के लिए 480.00 लाख का प्रावधान। चंदखुरी से शिवनाथ नदी मार्ग का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहितः लंबाई 6.50 कि.मी. के लिए 480.00 लाख का प्रावधान। निकुम खुर्सीपार भोथली मार्ग लंबाई 6.00 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्यः 480.00 लाख का प्रावधान है।

ग्राम कोनारी भरदा अलबरस निकुम मार्ग का निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित लंबाई 10.40 कि.मी.: 400.00 लाख का प्रावधान। बोरई से भरदाडीह (मनगट्टा) मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. में निर्माण कार्यः 380.00 लाख का प्रावधान। थनौद गौठान से बुढ़ार नदी तक पहुंच मार्ग निर्माण कार्य पुल-पुलिया सहित लंबाई 2.70 कि.मी.: प्रावधान। बोरई मनगट्टा मार्ग निर्माण कार्य पुल पुलिया सहित लंबाई 2.40 कि.मी.: 240.00 लाख का प्रावधान। थनौद कोलिहापुरी मार्ग लंबाई 4.80 कि.मी. का चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्यः 240.00 लाख का प्रावधान है।

प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए अधोसंरचना और अवसरों का विस्तार हमारी प्राथमिकता — मुख्यमंत्री साय

मुलाकात

मुख्यमंत्री साय से पूर्व क्रिकेट कप्तान कपिल देव ने की सौजन्य मुलाकात, खेल विकास पर हुई सार्थक चर्चा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से नया रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने सौजन्य मुलाकात की।

मुख्यमंत्री ने कपिल देव को बेल मेटल से बनी प्रतिकृति, पुण्यभूमि छत्तीसगढ़ कॉफी टेबल बुक भेंट कर उनका अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने, आधुनिक खेल अधोसंरचना के विकास, अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केंद्र तथा प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार करने जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने राज्य सरकार द्वारा खेलों के प्रोत्साहन और खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए अधोसंरचना, प्रशिक्षण और अवसरों का विस्तार सरकार की प्राथमिकता है।

पूर्व कप्तान कपिल देव ने छत्तीसगढ़ में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की सराहना करते हुए कहा कि सुरक्षा, विश्वास और विकास के इस माहौल में प्रदेश की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट मंच प्राप्त होगा तथा छत्तीसगढ़ सुरक्षित, समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ेगा।

पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में वाहन की टक्कर से बछड़ा घायल, गौ-सेवकों की तत्परता से बची जान

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शहर के पुराना बस स्टैंड स्थित चाय चेप्टर शॉप के पास एक बछड़े को अज्ञात वाहन चालक द्वारा टक्कर मार दिए जाने की घटना सामने आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से बछड़ा सड़क पर घायल अवस्था में तड़पता रहा, जिससे मौके पर कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

घटना की सूचना मिलते ही सुनील सेन अपने गौ-सेवक साथियों अशुल कासर एवं सत्यम मिश्रा के साथ तत्काल मौके पर पहुँचे। तीनों ने बिना देर किए घायल बछड़े को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था की। स्थानीय पशु चिकित्सक की सलाह से आवश्यक दवा और देखभाल की गई। गौ-सेवकों की तत्परता और सेवा भाव के चलते बछड़े की हालत में तेजी से सुधार हुआ। ईश्वर की कृपा और समय पर उपचार से अब बछड़ा पूर्णतः स्वस्थ बताया जा रहा है। क्षेत्रीय नागरिकों ने भी गौ-सेवकों के इस कार्य की सराहना की और कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज के लिए प्रेरणास्रोत हैं।

गौरतलब है कि शहर में तेज रफ्तार वाहनों के कारण आए दिन मवेशी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में यातायात नियंत्रण और गति सीमा का कड़ाई से पालन कराने की मांग की है।

सिंचाई, शहरी सुधार और प्रशासनिक सख्ती की पहचान रहे वरिष्ठ आईएएस विकास संकेतकों पर सीधे सीएम को करेंगे रिपोर्ट

विकास की कमान अनुभवी हाथों में : गणेश शंकर मिश्रा बने नीति आयोग उपाध्यक्ष, मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा को राज्य नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया जाना प्रशासनिक हलकों में एक निर्णायक और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है। नीति आयोग को राज्य के विकास एजेंडे के केंद्र में लाना चाहती है।

सूत्रों के अनुसार आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में मिश्रा राज्य के प्रमुख विकास संकेतकों पर सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे। यह व्यवस्था नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच अंतर कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसे राज्य सरकार के 'अंजोर छत्तीसगढ़' विजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-2047 लक्ष्य से भी जोड़ा जा रहा है।

'बुल्डोजर प्रशासक' जिनकी कार्यशैली ने विद्याचरण शुक्ल को प्रभावित किया

मिश्रा का प्रशासनिक करियर अनेक निर्णायक हस्तक्षेपों के लिए जाना जाता है। रायपुर नगर निगम में 1995 में महापौर प्रणाली लागू होने से पहले वे अंतिम प्रशासक रहे, जहाँ अवैध अतिक्रमण हटाने, नगरीय सुधार और प्रशासनिक अनुशासन स्थापित करने की कठोर कार्रवाइयों ने उन्हें "बुलडोजर प्रशासक" की पहचान दिलाई। मात्र पाँच माह के अल्प कार्यकाल में पाँच हजार से अधिक अतिक्रमण हटाए गए-एक ऐसा अभियान जिसे रायपुर के शहरी प्रबंधन और निगम प्रशासन के इतिहास में स्वर्णिम दौर के रूप में याद किया जाता है। उनका यह निर्णायक और परिणामोन्मुख नेतृत्व तत्कालीन केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री तथा छत्तीसगढ़ की राजनीति के प्रभावशाली नेता विद्याचरण शुक्ल को इतना प्रभावित कर गया कि उन्होंने मिश्रा को अपनी टीम में शामिल कर दिल्ली बुला लिया।

योजनाओं से बना विकास का रिकॉर्ड, मोदी ने भी सराहा

जल संसाधन विभाग में रहते हुए उन्होंने 'अभियान लक्ष्य भागीरथी' के माध्यम से एक वर्ष से काम समय में अभूतपूर्व सिंचाई क्षमता सृजित की, जिससे राज्य के कृषि ढांचे को नई मजबूती मिली। इस पहल की राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सचिव के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने अल्प अवधि में ही लाखों घरों तक नल-जल कनेक्शन पहुँचाने का व्यापक अभियान संचालित किया। इसके परिणामस्वरूप पेयजल उपलब्धता में ऐसी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो पिछले 70 वर्षों में हुए कुल विस्तार से भी अधिक दर्ज की गई।

बतौर आबकारी विभाग के प्रमुख, मिश्रा ने शराबबंदी के विषय पर सामाजिक जागरूकता और प्रशासनिक पहल-दोनों को समान रूप से आगे बढ़ाया, जिसे उनके जनोन्मुख दृष्टिकोण का सशक्त उदाहरण माना जाता है। उनके कार्यकाल में पहली और अब तक अंतिम बार ऐसा हुआ कि 350 से अधिक शराब दुकानों को बंद किया गया, और तत्कालीन सरकार ने आंशिक मद्यनिषेध की दिशा में ठोस व गंभीर कदम उठाए।

जिलों में कलेक्टर रहते हुए बदली प्रशासन की धार

राजनांदगांव में कलेक्टर रहते हुए मिश्रा ने बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाकर पाँच सौ से अधिक बाल विवाह रुकवाए और पंचायत स्तर पर स्वच्छता एवं जनभागीदारी का मॉडल विकसित किया। सन 2005 में, एक ओर जहां अविभाजित मध्यप्रदेश क्षेत्र के किसी जिले का खाता भी नहीं खुला था, छत्तीसगढ़ का राजनंदगांव अकेला ऐसा जिला था जिसके 12 ग्राम पंचायतों को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉ ए.पी.जे अब्दुल कलाम द्वारा स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। नक्सल प्रभावित बस्तर में उन्होंने कलेक्टोरेट को 'गांधी सेवा सदन' के रूप में विकसित कर प्रशासन को जनता के लिए अधिक सुलभ और संवेदनशील बनाने का प्रयास किया। इस पहल को प्रशासनिक मानवीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कदम माना गया।

नीति आयोग में अनुभव का उपयोग

प्रशासनिक विश्लेषकों का मानना है कि जिलों से लेकर सचिवालय तक विविध जिम्मेदारियों का सफल निर्वहन कर चुके अधिकारी के रूप में मिश्रा ने राज्य की चुनौतियों और संभावनाओं को केवल समझा ही नहीं, बल्कि उन पर ठोस परिणाम देने की क्षमता भी सिद्ध की है। यही कारण है कि नीति आयोग में उनकी भूमिका मात्र सलाह तक सीमित नहीं मानी जा रही, बल्कि विकास की दिशा निर्धारित करने वाली एक सक्रिय और निर्णायक भूमिका के रूप में देखी जा रही है।

गणेश शंकर मिश्रा की नियुक्ति को छत्तीसगढ़ की विकास रणनीति को प्रशासनिक अनुभव और संस्थागत ताकत देने की पहल के रूप में देखा जा रहा है-जो राज्य को विकसित भारत-2047 के लक्ष्य में मजबूत योगदानकर्ता बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

मुरागांव में खुशी की लहर, बांटी मिठाईयां

छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष पद पर सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी गणेश शंकर मिश्रा की नियुक्ति तथा इस पद को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिए जाने की खबर मिलते ही उनके गृह ग्राम मुरा में खुशी की लहर दौड़ गई। ग्रामीणों ने इसे पूरे गांव और क्षेत्र के लिए गौरव का क्षण बताते हुए मिठाई बांटी और एक-दूसरे को बधाई दी।

गांव के चौक-चौराहों पर लोगों ने एकत्र होकर मिश्रा की प्रशासनिक उपलब्धियों को याद किया और कहा कि गांव से निकले व्यक्ति को राज्य स्तर पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलना पूरे क्षेत्र का सम्मान है। बुजुर्गों ने कहा कि मिश्रा हमेशा अपने मूल गांव से जुड़े रहे हैं, इसलिए उनकी यह उपलब्धि गांव के हर परिवार की खुशी बन गई है। स्थानीय युवाओं ने इसे प्रेरणा का स्रोत बताते हुए कहा कि सार्वजनिक सेवा और परिश्रम से कोई भी व्यक्ति ऊंचाई हासिल कर सकता है। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि कैबिनेट मंत्री दर्जे के साथ यह जिम्मेदारी मिलना दर्शाता है कि राज्य सरकार मिश्रा के अनुभव पर भरोसा करती है।

दिनभर गांव में उत्सव जैसा माहौल रहा और लोगों ने उम्मीद जताई कि मिश्रा अपने नए दायित्व में भी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

"रफी की आवाज" मनोहर ठाकुर शनिवार को स्टील क्लब में

भिलाई। छत्तीसगढ़ में रफी की आवाज के नाम से मशहूर गायक मनोहर सिह ठाकुर शनिवार 28 फरवरी की शाम स्टील क्लब में अपन प्रस्तुति देंगे। स्टील क्लब शासी निकाय के सचिव डी विजिथ, कोषाध्यक्ष अजय पांडे एवं मेटलर्जिकल म्यूजिक मेकर्स के अध्यक्ष ज्ञान चतुर्वेदी ने बताया कि कार्यक्रम संध्या 6.30 बजे प्रारंभ होगा जिसमें 3एम के कलाकार भी प्रस्तुति देंगे। सेफी चेयरमैन तथा बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एनके बंछोर कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि होंगे।

नक्सल विरोधी अभियान : नक्सलियों का डंप विस्फोटक जवानों ने किया जब्त

नई दृष्टिबिंदु / नारायणपुर

जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा डंप किए गए भारी मात्रा में हथियार के साथ दैनिक उपयोग की सामग्री तथा मेडिकल वस्तुएं बरामद की है।

नारायणपुर एसपी रॉबिंसन विकास गुड़िया ने बताया कि विश्वसनीय सूचना पर त्वरित एवं एवं सुनियोजित एडीपी ऑपरेशन संचालित करने के दौरान ग्राम कुमुराडी क्षेत्र में नक्सली ठिकाना से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, आधुनिक एवं इंप्रोवाइज्ड हथियार तथा मेडिकल सामग्री एवं अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुएं बरामद हुए हैं। 25 फरवरी को विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर कार्वाई करते हुए सीओबी मंदोडा, 53 वीं बटालियन आईटीबीपी और पुलिस बल के जवानों की एरिया डॉमिनेशन पेट्रोलिंग पार्टी ग्राम कुमुराडी के जंगल पहाड़ की ओर रवाना हुई थी। इस दौरान सघन सर्च ऑपरेशन में जवानों ने नक्सलियों के एक ठिकाने में छिपाकर रखे गए डंप को बरामद किया।

जप्त सामग्रियों में प्रेशर कॉर्ड, सेफ्टी फ्यूज, अरिंज फ्यूज, लगभग 35 किलोग्राम सुतली बम, 38 किलोग्राम उर्वरक पाउडर (भूरा), 18 किलोग्राम इम्प्रोवाइज्ड विस्फोटक, 2.5 किलोग्राम चारकोल, 5 एएमएन पाउच, 1 इम्प्रोवाइज्ड रॉकेट लॉन्चर, 13 रॉकेट लॉन्चर सेल, 19 मोर्टार सेल (भारी), 11 मोर्टार सेल (हल्का), 1 बीजीएल लॉन्चर (इम्प्रोवाइज्ड-बड़ा), 1 बीजीएल लॉन्चर (इम्प्रोवाइज्ड - छोटा), 8 बीजीएल कारतूस (मध्यम), 15 बीजीएल कारतूस (छोटा), 12 बीजीएल कारतूस (बड़ा), 70 लंबी दूरी बीजीएल राउंड, 55 छोटी दूरी बीजीएल राउंड, 2 इम्प्रोवाइज्ड हैंड ग्रेनेड और चिकित्सकीय सामग्री एवं दवाइयां शामिल है।

आंदोलन दुकानों का आवंटन न करने के विरोध में जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा

मदर्स मार्केट में दुकान आवंटन को लेकर आप ने किया प्रदर्शन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

आम आदमी पार्टी ने आज भिलाई नगर निगम के सामने धरना दिया धरने का विषय मदर्स मार्केट में दुकानों का आवंटन न करने के विरोध में यह प्रदर्शन कर जिलाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा। भिलाई निगम आयुक्त ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे है ने कई बार आवेदन दिया कि महिलाओं के उत्थान के लिए बने मदर्स मार्किट में दुकानों का आवंटन करे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया।

मेहरबान सिंह ने भाजपा से सवाल किया की क्या भिलाई निगम आयुक्त को हटाने का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप करेंगे? ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है क्योंकि कुछ दिन पूर्व भाजपा ने प्रेस वार्ता करके की आयुक्त राजीव पांडे को हटाने की बात कही थी कुछ दिन बाद कांग्रेस वालों ने भी आयुक्त को हटाने की बात कही। अब सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में सरकार किसकी है भाजपा की है तो आयुक्त हटाने में समस्या क्या है? क्या आयुक्त को हटाने का ऐलान भी डोनाल्ड ट्रंप करेंगे?

जसप्रीत ने कहा कि करोड़ों रुपए खर्च करके विधायक निधि से जनता के टैक्स के पैसे से जो पुराना प्रगति मार्केट था उसको रिनोवेट किया गया और मदर मार्केट का नाम दिया गया। इस उद्देश्य से की महिलाओं को रोजगार मिलेगा मदर मार्केट में कुल 30 दुकान हैं इन 30 दुकानों में तीन दुकान अलग-अलग लोगों को दी गई है, लेकिन बिना किसी प्रक्रिया के उन दुकानों को दिया गया है जिसे अवैध कब्जा माना जा सकता है।

इन 30 दुकानों के आवंटन से मिनिमम अगर एक दुकान का किराया 5000 भी माने तो हर माह लगभग डेढ़ लाख रुपये निगम को राजस्व मिल सकता था, लेकिन पिछले कई वर्ष बीत जाने के बाद भी मदर मार्केट को ना महिलाओं को आवंटित किया गया नहीं अन्य किसी उद्देश्य के लिए रास्ता खोला गया।

अविनाश ने कहा पुराना मार्केट प्रगतिशील मार्केट जब जर्जर हो चुका था और रिनोवेट करने की कार्रवाई शुरू हुई तो उसे मार्केट में तीन लोगों को जबरदस्ती वहां से हटाया गया था जिनका केस उच्च न्यायालय में लंबित है हमारी जानकारी के अनुसार वैशाली नगर विधायक भिलाई नगर विधायक तथा महापौर के द्वारा अपने-अपने लोगों को आवंटन दुकान आवंटन करने की जिद में यह मामला लंबित है। सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्तमान में जो दुकान संचालित हो रही हैं। उनका विधिवत आवंटन नहीं किया गया है। कई लोगों ने आवंटन के लिए आवेदन देने पर उनको गोल-माल जवाब देकर के मामला रफा दफा कर दिया गया।

आम आदमी पार्टी क्या भाजपा कांग्रेस नेताओं द्वारा अपने अपने समर्थकों को दुकान आवंटित कराने की होड़ में मामला लंबित है? रिकेश सेन की यह उनकी संपत्ति होती तो वह ऐसे छोड़ देते क्या? देवेंद्र यादव की अपनी संपत्ति होती तो क्या वैसे छोड़ देते महापौर नीरज पाल की यह संपत्ति होती तो क्या यह छोड़ देते? भिलाई निगम आयुक्त अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं। जिस कारण से इन दुकानों का आवंटन विधि अनुसार नहीं हो पा रहा है।

डॉ. अग्रवाल ने कहा सी मार्किट में करोड़ों रुपए जनता टैक्स के पैसे को फूंक दिया गया जवाबदेही तय हः 45 दिनों के अंदर अगर भिलाई निगम कोई निर्णय नहीं बलेटा है तो आम आदमी पार्टी मजबूरन आंदोलन करने उतरेगी। उपस्थित सदस्य मेहरबान सिंह, के ज्योति, पूर्ण कुलबीर, शिव शेट्टी, जसप्रीत सिंह, सोनू यादव, डॉ. एसके अग्रवाल, के ज्योति सुजाता, देवेंद्र बिजलेकर रऊफ अंसारी, राजकुमार, अविनाश छबि मनीष मिश्रा, कृत राम, तुलसी राम, धर्मेंद्र चौधरी आदि शामिल थे।

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 यह हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंद स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवा कर। 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से प्रकाशित संपादक आलोक तिवारी मो. 7415469100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारण न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।